साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 49 05 - 11 दिसंबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

सौर ऊर्जा धारती बचाने की चुनौती पृष्ठ-6

चुनौती बनता जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य पृष्ठ-7

लाखों लोगों की क़ुर्बानी के बाद मिलने वाली 'आज़ादी'

फ़िल्म अदाकारा कंगना राणावत की नज़र में है

भीख

क्या मोदी सरकार इस 'भीख' का जश्न मना रही है?

मोदी जी अब बहुत हो चुका, आप की चुप्पी ही आप के भक्तों को बल पहुंचा रही है उनकी बदज़बानियों पर पाबंदी लगाना अब आप की ज़िम्मेदारी है।

1757 भारत के इतिहास का वह वर्ष है जब प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल रॉबर्ट क्लाइयू के बीच फैसला करने वाली लड़ाई हुई और जिसमें अपनो की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ी साम्राज्य का देश पर पंजा और मज़बूत हो गया मगर लड़ाई की यह चिंगारी एक शताब्दी बाद अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी जाने वाला देशव्यापी आंदोलन स्वतंत्रता के लिए ज्वाला बनकर सामने आया।

प्लासी की लड़ाई के ठीक एक दशक बाद 1857 में एक अहम घटना घटी जिसे अंग्रेजी साम्राज्य ने गदर का नाम दिया जबकि असल में यह देश की राष्ट्रीय स्तर का पहली आज़ादी की लड़ाई थी जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई, इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह ज़फर को बनाया गया था और हालांकि आरंभिक सफलताओं के बाद यह स्वतंत्रता आंदोलन कुछ असबाब की वजह से असफल हो गया था और पूरा देश अंग्रेजी साम्राज्य के हाथ में आ गया, मगर 1857 के बाद शहीदों के खून से जो लाइनें लिखी गई थी उसने बाक़ायदा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी।

इस नाकाम स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफ़रत पैदा कर दी। स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों की ज़ालिमाना करवाईयों ने इस नफ़रत की आग में तेल का काम किया। यह नफरत और गुस्सा जब अपने उच्च स्तर पर पहुंचा था उसी समय एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ई. में एक संगठन 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की स्थापना की, कांग्रेस का पहला इजलास 28 दिसंबर 1885 को मुम्बई में हुआ जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चन्द्र बनर्जी ने की थी। इसमें केवल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। जल्द ही दृष्टिकोणीय मतभेद की वजह से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग उन लोगों का था जो संवैधानिक तरीक़ों से भारतीयों के हालात बेहतर करना चाहते थे उनका ब्रिटिश की इंसाफपसंदी में पूरा यकीन था और उन लोगों का उद्देश्य कभी भी पूरी आज़ादी नही रहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, आदि इस समूह के अहम सदस्य थे। दूसरी ओर थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दीन चन्द्रपाल आदि जो भारत की संपूर्ण आज़ादी की बात करते थे और आख़िरकार यह मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आए और कांग्रेस दो भागों में बंट गयी। 1914 में लखनऊ समझौते में यह दोनों धड़े दोबारा एक हो गये।

इसी बीच श्रीमति ऐनी बेसंट ने तिलक के साथ मिलकर 1915 में होमरुल आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य भारतीयों को उनकी पैदायशी अधिकार 'स्वराज' यानि अपनी सरकार बनाना था। 1915 में ही महात्मा गांधी भारत लौटे, 1916 में उन्होंने अहमद आनंद के पास साबरमती में आश्रम की स्थापना की। भारत की जंगे आजादी में गांधी जी का प्रवेश बिहार के चम्पारण जिले से हुआ। वहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर अंग्रेज़ बहुत अधिक अत्याचार करते थे गांधी जी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, मज़हरूल हक़, आचार्य जे.बी. कृपलानी आदि के साथ 1917 में आवाज़ उठाई और आखिरकार सरकार को किसानों के कुछ मसायल सुलझाने पड़े।

अंग्रेज़ों के अत्याचार ने 1919 में एक और करवट ली। रोलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पास हुआ जिस के अनुसार जिस वयक्ति पर देशद्रोह का शक हो, उसको पकड़कर बग़ैर मुक़दमा चलाए दो वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। उसी वर्ष 13 अप्रैल को खास

फिल्म एक्ट्रेस कंगना राणावत भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मोदी सरकार से पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद कहा है कि 1947 में देश को आज़ादी नहीं भीख मिली थी। असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, जो पूरी तरह देश की आज़ादी के लिए क़ुर्बान हो जाने वाले लाखों मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन ही नहीं बल्कि देश के साथ खुली गद्दारी है।

बैसाखी वाले के दिन जलियावाला बांग में अधिवेशन की जनरल डायर को असंवैधानिक बताकर अनेक निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। कई सौ लोग मारे गए जिन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

सितम्बर 1919 में अली बिरादरान यानि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौक़त अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान और मौलाना हसरत मोहानी के नेतृत्व में ऑल इंडिया ख़िलाफ़त कमेटी की स्थापना हुई। 24, नवंबर 1919 को दिल्ली में ख़िलाफ़त कमेटी का अधिवेश हुआ जिसमें गांधी जी को बुलाया गया और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की पूरी हिमायत और असहयोग आंदोलन के साथ-साथ इस आंदोलन का भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अहम रोल रहा है।

सितम्बर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन की पेशकश की। सी.आर.दास पंडित मालवीय, दीन चन्द्रपाल चौरा चौरी में 05 फरवरी 1922 को कांग्रेस और ख़िलाफ़त कमेटी के वर्करों ने एक जुलूस निकाला, जुलूस में शामिल लोगों के साथ पुलिस की बदसलूी पर भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिस के नतीजे में लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गये। इस घटना ने गांधी जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने 12 फरवरी को तहरीक वापस ले ली।

08 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए कमीशन बनाया। सर साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इसके बायकॉट का फैसला किया गया। 03 फरवरी 1928 को जब कमीशन मुम्बई पहुंचा तो पूरी तरह हड़ताल थी और कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाए गये ''साइमन गो बैक'' का नारा चारों और गूंज रहा था। साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में लाहौर में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा जिस से उनकी मौत हो गयी।

मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गयी, जुलाई 1923 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गयी, नेहरू रिपोर्ट पर सोच विचार के लिए अगस्त 1928 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस और मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने 'सम्पूर्ण स्वराज' को कांग्रेस का उद्देश्य बताया।

फिर जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशात मंज़ूर न करने की वजह से संपूर्ण स्वराज की करारदाद पास की गयी, 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय तिरंगा लहराया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया।

स्वतंत्रता का यह आंदोलन इतनी शिद्दत से लड़ा गया कि भारत के कुछ भागों में ब्रिटिश सरकार फेल होने लगी। बंगाल के लोकमान्य तिलक, यूपी के बलिया और महाराष्ट्र के सतारा ज़िलों में क़ोमी हुकूमत भी बन गयी थी। ब्रिटिश हुकुमत ने इस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश की और ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया लेकिन आंदोलन बढ़ता ही गया और उसने हिंसा का रूप धारण कर लिया और आखिरकार यह आंदोलन बलपूर्वक कुचल दिया गया। 'भारत छोड़ो आंदोलन' की शिद्दत

बाक़ी पेज 11 पर

पाकिस्तान में न्यायपालिका बनाम मीडिया

पाकिस्तान को पत्रकारों के लिए ख़तरनाक देश कहा जाता रहा है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वह 180 देशों में 145वें स्थान पर है लेकिन पिछले दिनों उस वक्त खलबली मच गई, जब एक बेहद सम्मानित और लोकप्रिय जज ने एक पत्रकार, अख़बार के मालिक और संपादक समेत एक मीडिया ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब किया। पूरी दुनिया और हमारे क्षेत्र के अधिकांश देशों में मीडिया पर शासन की तीखी नज़र है और पाकिस्तान भी इसका कोई अपवाद नहीं है।

गिलगिट बाल्टिस्तान के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश राणा मोहम्मद शमीम ने दावा किया है कि वह न्यायिक कदाचार के गवाह हैं, जब उनके सामने फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने एक अन्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीएमएल (एन॰) प्रमुख नवाज़ शरीफ़ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को ज़मानत न दी जाए और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति न दी जाएं। न्यायमूर्ति शमीम का आरोप है कि साकिब निसार ने हाईकोर्ट के जज को फोन कर दोनों की ज़मानत याचिका ख़ारिज करने के लिए कहा। ज़ाहिर है, साकिब निसार ने इससे इंकार किया है कि उन्होंने कभी अपने प्रभाव का ग़लत इस्तेमाल किया है। न्यायमूर्ति शमीम ने अपना यह खुलासा एक विस्फोटक शपथपत्र के ज़रिये पेश किया। राणा मोहम्मद शमीम के पूरे हलफनामे को एक पत्रकार ने अंग्रेजी दैनिक द न्यूज़ इंटरनेशनल और उसके सहयोगी प्रकाशन *जंग* में फिर से प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में मोहम्मद शमीम की ओर से पुष्टि भी की गई है। लेकिन मोहम्मद शमीम के आरोपों के पीछे की सच्चाई की जांच के लिए न्यायिक जांच का आदेश देने के बजाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने तुरंत रिपोर्टर, संपादक और द *न्यूज* और *जंग* समूह के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा। राणा मोहम्मद शमीम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सोशल मीडिया पर इस हैरानी जताई गई। उस पर मीडिया समूह के लिए जहां बहुत समर्थन दिखा, वहीं एक बेहद लोकप्रिय और सम्मानित मुख्य न्यायाधीश की आलोचना हुई, जिन्होंने प्रकाशन समूह को अवमानना नोटिस जारी किया। मैंने तब टवीट किया था, 'मैं अतहर मिनल्लाह को लंबे समय से जानती हूं। वह एक अच्छे इंसान और सम्मानित जज हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को विश्वसनीयता दी। लेकिन ऐसा लगता है कि वह घबरा गए हैं और जल्दबाज़ी में उन्होंने ऐसा किया है, जबकि न्यायिक व्यवस्था का मज़ाक़ उड़ाने वाले उनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं। उनके तर्क कमज़ोर है। सूचना देने वाले को सज़ा देना सही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही अजीब टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च न्यायपालिका की अखंडता से ज़्यादा नहीं। उनकी यह टिप्पणी असंगत हैं, क्योंकि मीडिया और न्यायपालिका मुल्क के दो स्तंभ हैं और कोई इसका आंकलन नहीं कर सकता कि कौन महत्वपूर्ण हैं। मुख्य न्यायाधीश ने एक और प्रश्न उठाया कि मरियम नवाज़ के मामले की सुनवाई इस सप्ताह अदालत में होनी थी और क्या इस ख़बर को मामले पर प्रभाव डालने के लिए प्रकाशित किया गया था? उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका में जनता का विश्वास को भी कम करता है। क्या मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार को भी तलब करेंगें और कारण बताओ नोटिस भेजेंगे, जो इस न्यायिक नाटक में मुख्य किरदार हैं? क्योंकि यह जानना ज़रूरी है कि क्या न्यायमूर्ति साकिब निसार ऐसा अपने दम पर काम कर रहे थे या उसके पीछे सत्ता प्रतिष्ठान का हाथ था। क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के ख़िलाफ़ हो गया था ताकि वह अब सार्वजनिक पद पर न रह सके। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मरियम नवाज़ के लिए भी अदालतों ने मुश्किलें खड़ी कर दी थीं।

अगर इस मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है और सच्चाई सामने आती है, तो इससे न्यायपालिका की अखंडता को बहुत नुकसान पहुंचेगा, लेकिन यह बाकी न्यायपालिका को भी प्रभावित होने से बचने के लिए एक मज़बूत संदेश दे सकता हैं यह तभी हो सकता है, जब सुनवाई स्वतंत्र हो और कहीं से कोई व्यवधान न हो। कोई भी मीडिया प्रकाशन से इसकी ख़बर का स्रोत नहीं पूछ सकता, क्योंकि मोहम्मद शमीम का जो हलफनामा प्रकाशित हुआ था, वह लंदन में एक खुला और सार्वजनिक दस्तावेज़ है। यदि इस्लामाबाद हाईकोर्ट चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों के बारे में पूरी जांच करने से परहेज़ करता है, तो वह जनता का विश्वास भी खो देगा। स्वतंत्र मीडिया द न्यूज़ *इंटरनेशनल* और *जंग* के पूर्ण समर्थन में सामने आया है ओर यह सवाल उठाया है कि अपने घर को व्यवस्थित करने के बजाय न्यायपालिका द्वारा मीडिया हाउस पर निशाना साधना आख़िर

बाक़ी पेज 11 पर

तालिबान शासित अफ़ग़ानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए रूस ने बढ़ाए क़दम

अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश की आधी से ज़्यादा आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। धन और अन्य संसाधनों के अभाव की वजह से अफ़ग़ान लोगों को पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। स्पूतनिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को निर्बाध मानवीय सहायता मुहैया कराएगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि अफ़ग़ानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करेगा। नेबेंजिया ने कहा कि रूस आने वाले कुछ दिनों में अफ़ग़ानिस्तान को भोजन से लेकर दवाओं सहित तमाम सहायता पहुंचाएगा, रूस ने हाल में अफ़ग़ानिसतान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा, ''इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता देना है।नेबेंजिया ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की भूमिका समर्थन करते हैं। रूस अफ़ग़ानिस्तान की मदद करने के लिए अपना योगदान देने को तैयार है। स्पूतनिक ने प्रतिनिधि के बयान के हवाले से कहा, 'हम मानवीय सहायता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मज़बूत करने में संयुक्त राष्ट्र की समन्वय भूमिका का समर्थन करते हैं, इसलिए हम इस उद्देश्य में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। वहीं, संयुकत राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को अति आवश्यक सहायता के त्वरित प्रावधान को सक्षम करने की दिशा में काम करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करने का इच्छुक हैं इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हाल के सालों में अफ़ग़ानिस्तान ने पहले ही बहुत रक्त और हिंसा देखी है, त्रिमूर्ति ने कहा, 'अफ़ग़ानिस्तान की आधी से अधिक आबादी खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहा है। लोगों को आपातकालीन स्तरों पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अफ़ग़ान के लोगों को बुनियादी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है।

प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली आदर्श बनकर दिखाएगी?

पिछले दिनों जैसे ही दुबई पहुंचे, हवाई अड्डे पर ही लगा कि हम किसी नई दुनिया में आ गए। पिछले कई दिनों से हमारी प्यारी दिल्ली गैस चैंबर में बंद पड़ी रही। हमारी कोशिश रहती है कि अपने गुरुग्राम के घर में ही क़ैद रहें। सारे दरवाज़े, खिड़कियां और उजालदान लगभग बंद ही रखते रहे और घर में रहते हुए भी मुखपट्टी (मास्क) लगाए रहते थे। हालांकि घर के बाहर और पीछे 20-22 बड़े पेड़ लगे हुए हैं और करीब 200 गमलों में तरह-तरह के पौधे लहलहा रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता था कि घर के बाहर निकले तो कहीं ज़हर की नदी में गोता न लगाना पड़ जाए।

सड़क के पार का दृश्य इतना धुंधला होता था कि कुछ देखा और न देखा एक बराबर हो जाता था। इसीलिए पिछले 10-12 दिनों से घंटे भर का प्रात: भ्रामण स्थगित ही रहा। इंटरनेट ने बताया कि यहां प्रदूषण अंक सिर्फ 48 है जबकि दिल्ली में वह 500 को छू रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में रात के वक्त वह 1000 तक चला जाता है।

कहा जा रहा है कि दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 20 तो अकेले भारत में ही हैं और दिल्ली उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं प्रदूषण के इस दौर में विदेश में कई मित्रों से बात हुई। लंदन, लॉस एंजिल्स, फ्लोरिडा, बर्लिन और ज्यूरिख में प्रदूषण अंक-50 के आसपास है। चीन जैसे देश के शहरों में 100 से कम है लेकिन हमारे शहरों में एशिया के बड़े देशों की हालत खस्ता है। ध्यान रहे कि दिल्ली भारत की राजधानी है और इस शहर में एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री भी रहे हैं और दो दो सरकारें चल रही हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, जैसे पॉवरफुल संस्थाएं हैं। यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने काफी कड़े शब्दों में उठाया है। उम्मीद है कि दोनों सरकारें कुछ कड़े कदम उठाएंगी। 2019 में भारत के लगभग 17 लाख लोगों की मौत का कारण यह ज़हरीली हवा है। अकेले दिल्ली में 17500 लोग प्रदूषण के शिकार हुए हैं। सरकारें तो कुछ न कुछ कदम उठा ही रही हैं, लेकिन असली काम आम जनता को करना है जो लोग अपने घर के आसपास पेड़ लगा सकते हैं वे लगाएं वरना हर घर के सामने पौधों के दर्जनों गमले सजे होने चाहिए। सप्ताह में कुछ दिन कार और स्कूटर चलाने की बजाय पैदल, मेट्रो और बस का इस्तेमाल करें। किसान भाई पराली न जाएं, इसका इंतज़ाम सरकार करे। कुछ दिन दिल्ली के लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन मौसम और ऐसे ही रहने की संभावना है, फिलहाल हमें प्रदूषण को कम करने के लिए हर स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। ❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

शांति और भाईचारा है भारत और पाक के विकास की गारंटी

15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी ऐसी सूरत में मिली कि देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था देश का यह विभाजन चूंकि नफ़रत और क़त्ल व बर्बादी के साए में हुआ था इसलिए दोनों देश आज़ादी के पहले दिन से ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े दिखते रहे हैं और बदकिस्मती की बात यह है कि आज जब कि इस विभाजन को 75 वर्ष बीत चुके हैं आज भी ज़ेहनी और फिकरी हालात लगभग वही है आज़ादी के बंटवारे के समय थे। विभाजन के नतीजे में आबादी के अदल-बदली के नतीजे में क़त्ल और हिंसा के जो दृश्य देखने को मिले थे वह किस क़दर भयानक थे आज भी उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हज़ारों निर्दोष लोग इस विभाजन का शिकार हुए और इस तरह लाखों की सम्पत्ति तबाह व बर्बाद हुई और दोनों देशों के लोगों के दिलों में नफ़रत और दुश्मनी का उस समय जो बीज बोया गया था आज वह एक वृक्ष की शक्ल ले चुका है। आज हल यह है कि मामूली सी चिंगारी भी अमन व शांति को खत्म करने के लिए काफी हैं अब पाकिस्तान भी दो भागों में बंट चुका है पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया। मगर अफसोस यह है कि भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश अभी तक अपने आपको विभाजन की ज़ेहनियत से बाहर निकाल पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। अभी पिछले दिनों ही में बंग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर किन्ही शरारती तत्वों के बेवकूफी के नतीजे में कुछ नासमझ मुस्लिम नौजवानों की ओर से मंदिरों पर हमले और उस पर प्रतिक्रिया के तौर पर त्रिपुरा में मुस्लिम इबादतगाहों की बेहुरमती और तोड़ फोड़ की जो घटनाएं पेश आई वह उसी नफ़रत और अदावत का प्रमाण है जो देश के विभाजन के समय एक ज़हर के रूप में उपमहाद्वीप के मुसलमानों के दिलों में डाला गया था और जो आज रह-रहकर तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। आज़ादी के बाद ही बहुत से बुद्धिजीवियों की यह राय थी कि इस विभाजन के नतीजे में दोनों देश जिस सूरतेहाल से गुज़र रहे हैं उसका हल यही है कि दोनों देश विभाजन की सच्चाई को मानते हुए और आज़ाद वजूद बाकी रखते हुए एक ऐसी कन्फेडरेशन के भागीदार बन जाए जो दोनों देशों के बीच जन्म लेने वाले विवाद के हल में मददगार हो सके।

भारत की आज़ादी के कुछ ही साल बाद समाजवादी नेता व चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया ने विचार रखा कि एक समान भारतीय संस्कृति के वाहक भारत व पाकिस्तान देशों का एक महासंघ बनना चाहिए जिससे दोनों देश आपसी विवाद निपटाते हुए अपने-अपने देश की अवाम के आर्थिक व सामाजिक विकास का कार्य सामूहिक रूप से कर सकें। उस समय इस प्रस्ताव का समर्थन भारतीय जनसंघ (भाजपा) के विचारक समझने जाने वाले नेता पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भी किया। इसके बाद इस प्रस्ताव के समर्थन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महान विचारक व नेता प्रोफेसर एम.वी. कामथ ने भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया परंतु 29 अप्रैल 2004 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन शीर्षस्थ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' को दिये गये एक साक्षात्कार में जब इसी प्रस्ताव को जीवित करते हुए यह कहा कि 'उनके विचार में भारत-पाक परिसंघ की कल्पना एक दिन अवश्य सच हो सकती है और एक दिन ऐसा ज़रूर आयेगा जब दोनों देश यह सोचेंगे कि बंटवारे से समस्याओं का अंत नहीं होगा। अत: क्यों न देश एक साथ आकर कोई महासंघ या ऐसा ही कोई अन्य संगठन बना लें।'

श्री एल.के. आडवाणी उस समय देश के उपप्रधानमंत्री थे और उन्होंने यह मत आधिकारिक तौर पर व्यक्त किया था। इससे पूर्व भारत की लोकसभा में भी पाकिस्तान के मुद्दे पर भी आडवाणी ने भारत पाक महासंघ के डॉ. लोहिया के प्रस्ताव का ज़िक्र किया था वर्तमान में जब कश्मीर में भारत की सेनाएं पाक समर्थित आतंकवादियों को साफ करने की मुहिम चला रही हैं तो आम हिन्दुस्तानी के दिमाग़ में यह बात उठ सकती है कि यदि जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के बावजूद खूनखराबा नहीं रुक रहा है और पाकिस्तानी अपनी खूरेंजी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है तो इसका अन्य हल क्या होना चाहिए।

ज़ाहिर है कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत व पाकिस्तान के बीच चार बार युद्ध हो चुका है। 1947, 1965, 1971 और 1999। मगर कश्मीर की समस्या जस की तस खड़ी हुई है और दोनों देशों के बीच रंजिश ताल्लुक़ात बने हुए हैं। मगर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान भारत से रंजिश क्यों मानता है जबकि 1947 से पहले उसकी सारी अवाम हिन्दोस्तानी ही थी। बंटवारा होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के प्रति कभी नि:स्वार्थ भाव से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और हर चंद कोशिश की कि वैर भाव समाप्त न हो। वस्तुत: यह वैर भाव दोनों देशों की अवाम की सांस्कृतिक एकता की क़ुर्बानी देकर बढ़ाया गया जिससे पाकिस्तान के वजूद की वजह बनी रहे। बेशक पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है मगर भारतीय उपमहाद्वीप में सुख शांति व समृद्धि बनाये रखने के उद्देश्य से पाकिस्तान यूरोपीय संघ जैसी नीति का अनुसरण करके भारत के साथ ही निरर्थक लगने लगे परंतु इस मार्ग में पाकिस्तान की फौज ही सबसे बड़ी बाधा है जो कश्मीर के नाम पर भारत और भारतीयों के विरुद्ध दुश्मनी का भाव जागृत रखना चाहती है। यह भाव पाकिस्तानी फौज धर्म मूलक हिन्दू मुसलमान के रूप में बनाती रही है।

ग़ौर करने वाला तथ्य यह भी है कि आज़ादी के बाद से अब तक युद्ध सोजो सामान पर पाकिस्तान ने ख़र्च किया है और उससे निपटने के लिए भारत को भी कितना ख़र्च करना पड़ा है? यदि यही पाकिस्तान ने अपने मुल्क की अवाम की तरक्क़ी पर लगाया होता तो आज उसके हाथ में भीख का कटोरा न होता और चीन ने उसे अपना गुलाम जैसा न बनाया होता? हक़ीक़त तो यही रहेगी कि पाकिस्तान कभी सैनिक मोर्चे पर भारत का मुक़ाबला नहीं कर सकता, बेशक पाकिस्तान ने भी परमाणु बम ही क्यों न बना लिया हो इसलिए पाकिस्तान को सोचना होगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह बर्बादी का रास्ता है क्योंकि चाह कर भी वह पाकिस्तान की उस हक़ीक़त को नहीं बदल सकता जो भारतीयता के रंग से आज तक सराबोर है। यह हिन्दोस्तानियत वही है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थी जब हिन्दू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज सरकार के ख़िलाफ़ जेहाद छेड़ा था।

भारत ने देश का बंटवारा होने के बावजूद पाकिस्तान की अवाम की भारतीयों के साथ रसूखदारी और दोनों मुल्कों की एक जैसी तहज़ीब के ख़्याल से कोशिश की कि अलग हो जाने के बावजूद दोनों मुल्कों में अमेरिका और कनाडा जैसे संबंध रहें। यही वजह थी कि पाकिस्तान बनने के बाद वहां पहले उच्चायुक्त श्री श्रीप्रकाश भेजे गये थे और पाकिस्तान ने भारत में ही जन्मे एक कूटनीतिज्ञ को अपना उच्चायुक्त दिल्ली में मुक़र्रर किया था। शुरू के कई सालों तक केवल परमिट लेकर नागरिक एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे और यहां तक कि लाहौर में होने वाले क्रिकेट मैच का आनंद भी ले लेते थे। भला कोई पूछे कि पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब में क्या अंतर है तो उत्तर यही मिलेगा कि पंजाबी संस्कृति दोनों ओर एक समान रूप से अपने शबाब में रहती है।

भारत पाकिस्तान महासंघ के विचार में इन सभी समस्याओं का अन्तिम हल इस प्रकार निहित हो सकता है कि दोनों देश मिलकर अपनी ज़मीनी ताक़त को आवाज़ देते हुए दुनिया में सिर उठाकर चलें। जब यूरोप के सभी देश मिलकर अपनी पहचान अलग-अलग क़ायम रखते हुए एक इकाई के रूप में अपने सर्वांगिण विकास के मार्ग खोज सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी अवाम की भलाई के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता और अपने सिर से आतंकवादी देश होने की तोहमत क्यों नहीं नहीं दुत्कार सकता।

आज विश्व स्तर पर भारत और पाकिस्तान की आर्थिक सूरतेहाल किसी से छीपी नहीं है। राजनैतिक और आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान भारत से भी कमज़ोर है और कर्ज़ में डूबा हुआ है, यह दोनों देश अपने स्रोत को अपने विकास पर खर्च करें तो न पाकिस्तान को चीन जैसे खुदगर्ज़ देश का हाथ थामना पड़े और न ही भारत को विश्व आर्थिक संगठनों के दबाव का शिकार होना पड़े। दुनिया के जिन देशों ने अमन शान्ति का यह फलसफा समझ लिया है वह बहरहाल आज विकास की डगर पर बहुत आगे निकल चुके हैं।❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त-100

एक दिन का वाक़िआ है कि मुल्के शाम के रहने वाले एक आदमी पर नज़र पड़ी, जो कह रहा था कि कअ़ूब बिन मालिक कौन है? किसी ने मेरी जानिब इशारा कर दिया तो उस ने मेरे हाथ में एक परचा दिया। उस परचे में ग़स्सान के बादशाह की जानिब से मेरे नाम पैग़ाम था: ''हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे आक़ा ने तुम से रूख़ फ़ेर लिया है, लिहाज़ा तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा बड़ा ऐज़ाज़ व इकराम करेंगे'' फ़रमाते हैं कि यह परचा पढ़ कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और फ़ाड़ कर फ़ौरन तनूर में डाल दिया कि यहाँ तक बात आगई कि ग़ैर मुझ से उम्मीद रखे, यह मतलब नहीं है कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम की ग़ुलामी मैं छोड़ दूँगा। फ़रमाते हैं कि रोते रोते मेरे आँसू ख़ुश्क हो चुके थे, एक दोस्त को पकड़ कर कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं मोमिन हूँ, फिर भी तुम बेरूख़ी इख़्तियार कर रहे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चालीस दिन के बाद पैग़ाम पहुंचा कि अपनी बीवीयों से भी अलग हो जाओ, चुनान्चे बीवीयों से भी अलग हो गए, हिलाल बिन उम"या की बीवी आई और कहने लगीं कि हज़रत मेरे शौहर तो बिल्कुल ही बूढ़े आदमी हैं अगर मैं न रहूँ तो उन्हें कोई खाना देने वाला भी नहीं है, हज़रत ने फ़रमाया कि खाना रख दिया करो साथ मत खाया करो। इन तीनों हज़रात पर 50 दिन इस तरह से गुज़रे कि ज़मीन बावुजूद वुसअ़त के तंग हो गई।

सहाबा-ए-किराम रज़ि अल्लाहु अ़न्हुम अजमईन ने पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के हुक्म की तामील इस तरह की कि अलफ़ाज़ में बयान नहीं किया जा सकता, पचासवीं शब में अल्लाह तआ़ला की जानिब से इन तीनों की तौबा का ऐलान हुआ, और क़ुरआन पाक में आयतें नाज़िल हुईं। फ़रमाया:

''अल्लाह तआ़ला ने पीछे रह जाने वाले आदमियों की तौबा क़ुबूल कर ली, यहाँ तक कि ज़मीन उन पर बावुजूद वुसअ़त के तंग हो चुकी थी और ख़ुद उन के जी भी तंग हो चुके थे, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं, मगर उसी के पास फिर अल्लाह तआ़ला उन पर मेहरबान हुआ ताकि वे रूजू हों, और बेशक अल्लाह तआ़ला ही हैं मेहरबान, रहम वाले।

इस आयत में अल्लाह तबारक व तआ़ला ने पूरा नक़्शा खींच दिया और उनकी तौबा का ऐलान फ़रमाया, रात को ये आयतें नाज़िल हुईं, सुबह को नमाज़ में पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने ऐलान फ़रमाया।

सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की जानिब से या तो अब तक पूरी तरह बायकाट जारी था या फिर उनका दूसरा अ़मल देखिये, जैसे ही तौबा का ऐलान हुआ, तो सहाबा में दौड़ लग गई कि उनको पहले जाकर कौन ख़ुशख़बरी सुनाये? यह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर अपनी छत पर बैठे हुए थे, मस्जिदे नबवी से दौड़ शुरू हुई, कोई सवारी पर चला, कोई पैदल चला, कोई घोड़े पर चला, और एक सहाबी ने तो पहाड़ पर चढ़ कर आवाज़ लगाई:

''कअ़ूब बिन मालिक ख़ुशख़बरी क़ुबूल कीजिये!''

उनकी आवाज़ सब से पहले मेरे कान में पड़ी। इस ऐलान के बाद फिर वही मुहब्बत, हमदर्दी और ख़ैर ख़्वाही उभर कर आ गई, और कअ़ूब बिन मालिक जब घर से चले हैं, तो रास्ते में हर जगह मुबारकबादियाँ मिल रही थीं, चुनान्चे पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में तशरीफ़ लाए। (जारी)

गाँधी की अर्थनीति नेहरू पटेल ने नहीं मानी

सच्चिदानंद सिन्हा

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा 92 वर्ष के हो गए हैं। दर्शन राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण संबंधी उनके लेखन का संग्रह हाल ही में आठ खंडों में छप कर आया हैं वह शहरों की आपाधापी से दूर बिहार के एक गांव में रहे हैं। गांधीवादी तरीक़े से बहुत कम संसाधनों के इस्तेमाल वाली जीवन शैली अपना रखी है। पेश उनसे हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- आप आज़ादी के आंदोलन को किस तरह देखते हैं? दुनिया के बाक़ी देशों के उपनिवेशवादी-विरोधी आंदोलनों के विपरीत यहां विचारधाराओं के बीच संघर्ष हिंसक लड़ाई में नहीं बदला। अलग-अलग विचार के लोग साथ काम करते रहे। किसी ने भी प्रतिद्वंदी विचार रखने वालों को ख़त्म करने की नहीं सोची। विचारों के इस अनोखे सहअस्तित्व को आप कैसे देखते हैं?

उत्तरः- आज़ादी के आंदोलन को सतत् विकास की एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन में विभिन्न विचारों के बीच जो समन्वय दिखाई देता है, वह गांधी जी का असर था। तिलक का अहिंसा में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन इसके बावजूद गांधी जी ने उनके निधन के बाद तिलक स्वराज फंड के लिए खूब काम किया।

यह सच है कि गांधी जी एकदम अलग राय रखते थे। वह ग्राम गणराज्य और छोटी अर्थ व्यवस्था चरखा करघा की बात करते थे। लेकिन इसे कांग्रेस के किसी और नेता ने क़बूल नहीं किया। नेहरू और पटेल ने भी नहीं। फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेहरू या पटेल ने गांधी जी से उनके नीति के विरोध की कोई नीति अपनाई। नेहरू या पटेल मिलकर सरकार चला रहे थे और अर्थ नीतियों को लेकर समान राय रखते थे। गांधी जी ने कभी अपनी नीतियों को उन पर लादने की कोशिश नहीं की।

उन्होंने कांग्रेस के भीतर भी विभिन्न विचारों को पनपने दिया। उनके साथ कई लोगों का वैचारिक टकराव हुआ। सुभाष चन्द्र बोस के साथ तो उनका वैचारिक टकराव इस हद तक गया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने पट्टाभि सीतारमैया को अपना समर्थन दिया। सुभाष बाबू के चुने जाने के बाद गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि पट्टाभि की हार मेरी हार है लेकिन इस टकराव के बाद भी उन दोनों के संबंध ऐसे थे कि सुभाष बाबू ने ही महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा। यह समन्वय हमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य नेताओं के बीच भी दिखाई देता है।

प्रश्नः- कई लोग मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच आर्थिक विचारों को लेकर गंभीर मतभेद थे। इनका कहना है कि नेहरू ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, वे गांधी जी की आर्थिक सोच से अलग थी। ये लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर गांधी जी की नीतियां अपनाई जातीं तो आज शायद हमारी अर्थव्यवस्था अलग तरह की होती..?

उत्तरः- यह सच है कि गांधी जी एकदम अलग राय रखते थे। वह ग्राम गणराज्य और छोटी अर्थ व्यवस्था चरखा करघा की बात करते थे। लेकिन इसे कांग्रेस के किसी और नेता ने क़बूल नहीं किया। नेहरू और पटेल ने भी नहीं। फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेहरू या पटेल ने गांधी जी से उनके नीति के विरोध की कोई नीति अपनाई। नेहरू या पटेल मिलकर सरकार चला रहे थे और अर्थ नीतियों को लेकर समान राय रखते थे। गांधी जी ने कभी अपनी नीतियों को उन पर लादने की कोशिश नहीं की। सच तो यह है कि अन्तिम दिनों में गांधी जी के सामने यह सब मामला गौण था। तब उन्हें लग रहा था कि अगर सांप्रदायिक आग बुझाई नहीं गई तो भारत एक मानवीय समाज के रूप में ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए वह उस आयु में नोआखाली के गांव गांव गए। वह देश के दूसरे हिस्सों में गए। उन्होंने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी। यह उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। उन्हें इस पर कोई ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या अर्थनीति है। उन्हें लग रहा था कि अगर यह आग नहीं बुझी तो भारत का विघटन हो जाएगा।

प्रश्नः- जब गांधी जी के आर्थिक विचारों की बात आई है तो यह प्रश्न उठेगा ही कि साम्यवाद भी उसी टेक्नोलॉजी के पक्ष में है, जिसे पूंजीवाद अपनाता है। क्या आपको नहीं लगता कि बराबरी वाला समाज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन की ज़रूरत है..?

उत्तरः- आधुनिक टेक्नोलॉजी में ग़ैर बराबरी अंतर्निहित है। एक आदमी ऊपर होता है और बाकी सब उसके मातहत। यह क्रम चलता है। कारखानों की व्यवस्था ऐसी ही है। रूसी क्रांति हो जाने के बाद भी यही स्वरूप रहा। राज्य का ढांचा ऐसा ही रहा। अगर इसे तोड़ना है तो टेक्नोलॉजी छोड़नी पड़ेगी। इसके बग़ैर हम बराबरी नहीं पैदा कर सकते हैं। गांधी जी के चरखे में ऊपर नीचे का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

गांधी प्रासंगिक हैं लेकिन हम इतना आगे निकल गए हैं कि एकदम से गांधी वाली व्यवस्था पर नहीं आ सकते। लेकिन ऊर्जा आधारित अर्थ व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो हम अपने ग्रह के विनाश को टाल भी नहीं सकते हैं। पृथ्वी बचानी है तो हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह ज़रूरी है कि हम छोटे और मध्यम दर्जे की टेक्नोलॉजी अपनाएं। जलवायु परिवर्तन के संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।

प्रश्नः- मार्क्स ने टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर कोई अलग राय नहीं रखी है। ऐसे में गांधी की प्रासंगिकता बढ़ जाती है..?

उत्तरः- मार्क्स ने पश्चिम में हुए आर्थिक विकास का अध्ययन किया। उन्होंने वहां के तनीकी परिवर्तनों का गहराई से विश्लेषण किया है। जलवायु परिवर्तन का सवाल बाद में सामने आया है। गांधी प्रासंगिक हैं लेकिन हम इतना आगे निकल गए हैं कि एकदम से गांधी वाली व्यवस्था पर नहीं आ सकते। लेकिन ऊर्जा आधारित अर्थ व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो हम अपने ग्रह के विनाश को टाल भी नहीं सकते हैं। पृथ्वी बचानी है तो हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह ज़रूरी है कि हम छोटे और मध्यम दर्जे की टेक्नोलॉजी अपनाएं। जलवायु परिवर्तन के संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ❑❑

हम परिवारों की प्राइवेसी सुनिश्चित करेंगे

एम॰ एल॰ खट्टर

हर परिवार को एक पहचान पत्र देने की कोशिश का उद्देश्य नीति निर्माण और शासन की डिलीवरी में गेम चेंजर बनना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बातचीत में बताया कि हरियाणा किस तरह इस पहल को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है जबकि कर्नाटक और तमिलनाडू जैसे राज्यों में यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया : मुख्य अंश :

प्रश्नः- नीति निर्माण में परिवार पहचान पत्र किसत रह गेम चेंजर होगा?

उत्तरः- भारतीय नागरिक की पहचान आधार कार्ड से होती है, एक यूनिक आइडी, जिससे लोगों को सीध डिलीवर करने में मदद मिलती है। फिर भी हमारा समाज व्यक्ति केन्द्रित नहीं है, यह परिवार केन्द्रित है लिहाज़ा एक परिवार पहचान पत्र ज़रूरी है।

प्रश्नः- क्या यह राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सीमित है या यह सबके लिए है?

उत्तरः- यह सबके लिए है। हरियाणा में 69 लाख परिवार हैं, जिनके ब्यौरे विभिन्न विभागों के पास हैं, भले ही वह पीडीएस लाभार्थी के रूप में हों, संपत्ति के पंजीकरण या कुछ दूसरे लाभ के लिए हों। काम डेटा में सहयोग और सफलता लाने का है। हमने इसे संस्थागत बनाने के लिए एक अलग विभाग, सिटीजन रिसोस इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआइडी) बना दिया।

प्रश्नः-आप डेटा कैसे जुटाते हैं?

उत्तरः- शुरू में परिवार का प्रमुख परिवार के आकार, नाम, आयु, संपत्ति और आय जैसी बुनियादी जानकारी खुद देता है। फिर उसे पांच सदस्यीय टीम प्रमाणित करती है। इस तरह जुटाया गया डेटा अटल सेवा केन्द्र पर फीड किया जाता है।

प्रश्नः- क्या आपने इस परिवार आइडी के साथ सरकारी योजनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया है.?

उत्तरः- हां, हमने 456 योजनाओं को पीपीपी के साथ जोड़ दिया हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम दुर्घटना सुरक्षा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम लघु परिवार व्यापार सम्मान निधि और पीएम श्रमजीवी सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, सब इस आइडी से जोड़ दी गई है।

प्रश्नः- यह आइडी लोगों के जीवन में किस तरह बदलाव लाएगा.?

उत्तरः- यह डेटाबेस हमें -आय के मामले में - राज्य के एक लाख सबसे ज़्यादा ग़रीब लोगों की पहचान करने और हमारे संसाधनों को उन्हें ऊपर उठाने में मदद कर रहा हे।

प्रश्नः- क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए परिवार का आइडी सार्थक है?

उत्तरः-नहीं, यह केवल राज्य की योजनाओं या उन योजनाओं के लिए हैं, जिनमें राज्य नागरिकों की ओर से योगदान करता है। हमने ऐसी 100 से ज़्यादा योजनाओं की पहचान की है, चाहे वह विवाह के लिए लड़कियों की सहायता हो या स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति। यह डेटा बदलता रहेगा।

प्रश्नः- आप परिवार की इकाई कैसे तय करते है?

उत्तरः- परिभाषा के मुताबिक परिवार में पति-पत्नी, बच्चे व उन पर निर्भर माता-पिता होते हैं, फिलहाल, हम सालाना 1.8 लाख रुपये से कम आय वाले बीपीएल परिवारों की पहचान कर रहे हैं, धीरे-धीरे हम उसमें परिवारों की प्रति व्यक्ति आय शामिल करेंगे। अगर किसी परिवार में तीन सदस्य हैं तो प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपये होगी, पर अगर उसमें छह सदस्य हैं तो यह 30,000 रूपये हो जाएगी।

प्रश्नः- आप इस तरह के डेटा की निजता की रक्षा कैसे करेंगे?

उत्तरः- यह डेटा एक जगह पर नहीं होगा। हमारे पास बुनियादी जानकारी होगी और बाकी डेटा अलग अलग होगा। सो अगर, स्वास्थ्य विभाग इस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलेगी। ❑❑

छोटी नदियाँ बड़े सवाल

हरियाणा के यमुनानगर के कनालसी गांव के निकट से एक नदी बहती है - थापना। लगभग 15 किलोमीटर लंबी यह नदी यमुना की सहायक नदियों में एक है। इस नदी की एक विशेषता यह है कि इसमें कुछ ऐसी प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है, जो प्रदूषिता पानी में नही रह पातीं। यानि इस नदी में प्रदूषण की स्थिति देश की कई प्रमुख नदियों जैसी नहीं है। मगर 2012 में इस नदी का अस्तित्व संकट में आ गया था। एक तो उस वर्ष बारिश उम्मीद से कम हुई। ऊपर से इलाके में विकास के नाम पर होने वाले कुछ निर्माणों ने सहायक धाराओं से '*थापना*' में आने वाले वर्षाजल का प्रवाह बंद कर दिया। नदी की स्थिति ने इलाक़े के कुछ संवेदनशील लोगों को चिंतित किया। किसी भी बड़ी नदी का प्रवाह तंत्र उसकी सहायक नदियों की स्थिति पर ही निर्भर होता है। अगर सहायक नदियां सूख जाएंगी तो मुख्यधारा का प्रवाह कैसे बना रह सकता है? आज अगर देश की कई प्रमुख नदियों की स्थिति शोचनीय है, तो इसका एक कारण है कि हमने सहायक नदियों, जिनमें बरसाती नदियों प्रमुख हैं - को बचाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

किसी नदी का इस तरह दम तोड़ना क्या होता है, यह उसके किनारे रहने वाले लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? आज से करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले तक लोगों के घर तक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था किसी सरकार या शासक की ज़िम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। उस समय लोगों को नदियों, कुओं, बावड़ियों, तालाबों या कुण्डों जैसे जलस्रोतों पर ही निर्भर रहना होता था। कहते हैं कि गरज बावली होती है। स्वार्थसिद्धि की आशा व्यक्ति के व्यवहार को किसी के प्रति संवेदनशील बना देती है जिस दौर में लोग जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे जलस्रोतों पर ही निर्भर करते थे, उस उमस इनकी पूजा की जाती थी, इन्हें प्रदूषित करना पाप माना जाता था। करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले नदी का लुप्त होना तो छोड़िए उसका रास्ता बदलना तक पूरे समाज को चिंता में डाल देता था।

2012 में जब '*थापना*' नदी में पानी बहुत कम हो गया तो नदी के किनारे रहने वाले कुछ संवेदनशील लोगों को उन मछलियों और अन्य जीवों की चिंता सताने लगी, जो नदी के पानी में रह रहे थे। एक पंचायत बुलाई गई। नदी किनारे जिन लोगों के खेत थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे सिंचाई के लिए नदी में ऐसी जगह पंप लगाएं, जहां अपेक्षाकृत पानी अधिक हो, ताकि कम पानी में रहने वाले जीवों को बचाया जा सके। हालांकि अकाल की आशंका मुंह बाए खड़ी थी, लेकिन कन्यावाला, मंडोली जैसे गांवों के किसानों ने यह मानते हुए कि मूक जीवों की प्राण रक्षा के लिए ऐसा करना पुण्य का काम होगा, पंचायत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर एक सेवानिवृत्त अधिकारी के '*यमुना जियो अभियान*' के तहत इस इलाके में बीस '*नदी मित्र*' मंडलियां गठित की गई। इन मंडलियों के सदस्यों ने इलाके के पांच सौ से अधिक लोगों को नदी संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया। लंदन की संस्था '*थेम्स रिवर रेस्टोरेशन ट्रस्ट*' का भी सहयोग इन कोशिशों को मिला। इलाके में रहने वाले नदी के प्रति जुड़ाव महसूस करें, इसलिए हर वर्ष सितंबर के आख़िरी रविवार को नदी का जन्मदिन मनाने की शुरुआत हुई। सारे प्रयासों ने रंग दिखाए ओर '*थापना*' नदी को बचा लिया गया।

छोटी नदियों को बचाने में स्थानीय लोगों का नदी से जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रामरा गांव में रहने वाले मुस्तकीम मुल्ला नामक युवक ने इस बात को महसूस करते ही यमुना की एक और सहायक नदी '*कथा*' को बचाने के लिए '*एक घर एक लोटा पानी*' अभियान चलाया था, जिसके तहत गांव के परिवारों से आग्रह किया गया था कि वे प्रतिकात्मक तौर पर अपने-अपने घरों से एक एक लोटा पानी नदी को समर्पित करें। इस अभियान ने इस लगभग 90 किलोमीटर लंबी नदी के प्रति लोगों की संवेदनाएं जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1830 में जब पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया तो सहारनपुर और रामपुर के मध्य एक बड़े हिस्से में नदी का प्रवाह बाधित हो गया। धीरे-धीरे नदी अनदेखी का शिकार होने लगी। नदी मित्र मंडली के सदस्यों ने महसूस किया कि अगर बरसात के दिनों में यमुना की बाढ़ के पानी को अनावश्यक न बहने दिया जाए और उसे किसी तरह '*कथा*' नदी में रोक लिया जाए। शुरुआत एक किलोमीटर के हिस्से में नदीतल में गहरी खुदाई करने से हुई। नदीतल में एक तालाबनुमा रचना बन गई और पानी संचय की मात्रा बढ़ गई। ऐसा नदी के प्रवाह क्षेत्र में कई स्थानों पर किया गया। अतिरिक्त पानी के प्रवाह को रोकने के लिए नदी जल में इन संरचनाओं के पास चेक डैम भी बनाए गए हालांकि 2017 में कम बारिश होने से लोगों के सपने बाधित हुए, लेकिन अंततः '*कथा*' नदी को बचाने की मुहिम रंग लाई।

सन 2007 में बंगलुरु में अचानक जलसंकट पैदा हो गया। शुद्ध जलापूर्ति का प्रमुख साधन थिप्पागोंडानहल्ली जलाशय में जल स्तर बहुत कम हो गया। इस जलाशय में जलापूर्ति का प्रमुख साधन कुमुदवती नाम की नदी हे। मगर कुमुदवती की अपनी हालत पतली थी। ऐसे में कुछ लोगों ने नदी से रेत निकालने और नदी के आसपास के इलाके में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्राचीन कल्याणियों (बावड़ियों) और अन्य जलस्रोतों के जीर्णोद्धार का काम किया। जब इलाक़े में जलस्तर बढ़ता है, तो नदी को भी अपना प्रवाह क़ायम रखने में मदद मिलती है। केरल के पलक्कड़ जिले के पल्लसेना गांव के निवासियों ने '*गायत्रीपुजा*' नामक नदी को बचाने के लिए नदी के प्रवाह क्षेत्र में जलस्तर बचाने के लिए ऐसे ही उपाय अपनाए। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी 'बृहत्तपुजा' भी कई स्थानों पर बहुत क्षीण हो गई थी। इस नदी के किनारे बसे पोक्कुटुकावो गांव में स्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्होंने नदी के पेटे और उसके आसपास जलसंग्रहण के लिए कुएं जैसी संरचनाएं बनाईं। उत्तर प्रदेश में '*मंदाकिनी*' और '*तमसा*' को बचाने के काम हुए हैं, जबकि सरकारी स्तर पर तेढ़ी, मनोरमा, पांडु, वरुणा, सासुर, अरिल, मोरवा, नाद, कम्रवती, बाण, सोत, काली, पूरवी, दाढी, ईशान, बूढ़ी गंगा और गोमती नदियों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। राजस्थान के जयपुर शहर में द्रव्यवती नाम की ऐतिहासिक नदी एक गंदे नाले में बदल गई थी। उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई और उसके किनारे एक रिवर फ्रंट विकसित कर उसे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में जोड़ा गया है।

सरकारी तंत्र की अपनी विवशताएं और ख़ामियां होती हैं। छोटी नदियों को बचाने के लिए सरकारी योजनाओं से अधिक आवश्यक है लोगों का नदियों के प्रति संवेदनशील होना। स्थानीय जुड़ाव के बिना नदियां उपेक्षित ही रहती है। लोग अगर नदी के सांस्कृतिक, सामाजिक, पौराणिक और आर्थिक महत्व को समझें तो नदियों को उपेक्षा से मुक्ति मिल सकती है। पंजाब की कालीबेई नदी का इतिहास स्वयं गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ था, लेकिन नदियों के प्रति उपेक्षा भाव की प्रवृत्ति ने कालीबेई को भी कुछ सालों पहले एक गंदे नाले में बदल दिया था। संत बलबीर सिंह सिच्चेवाल की पहल पर लोगों का समर्थन मिला और कभी उपेक्षा के अंधेरे में रहने वाली कालीबेई नदी आज लोगों की श्रद्धा और पर्यटन का केन्द्र है। छोटी नदियों को बचाया जा सकता है, बशर्ते स्थानीय लोग उनके प्रति अपनापन महसूस करें। ❑❑

रोज़गार .....

रोमांच और साहस भरा कैरियर ओशेनोग्राफी

आजकल रोज़गार के साधन सीमित होते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं, फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र है जिसकी कम लोगों को जानकारी है। ऐसा ही एक क्षेत्र है ओशनो। समुद्र की गहराईयों को मापना, उसके अंदर के जीवन को महसूस करना आज भी इंसानों के लिए किसी कठिन चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आबादी की ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ रही हैं, समुद्री संपदा का उपयोग आवश्यक हो गया है। यही वजह है कि देश विदेश की विभिन्न तेल कंपनियां ऑफशोर ऑयल एक्सप्लेरेशन में जुटी हैं। लिहाज़ा ओशन इंजीनियिरंग के ज़रिये आप भी इस फील्ड में क़दम रख सके हैं। यहां नेवल डिजाइन, शिपयार्ड, ऑफशोर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, फाइनेंशियल एनालिसिस और मार्केटिंग सेक्टर में आपके लिए अनेक मौक़े हैं।

क्या है ओशेनोग्राफी

ओशेनोग्राफी के कई क्षेत्र हैं। फिजिकल ओशनोग्राफी के तहत समुद्री और मौसम के संबंधों को जानने की कोशिश की जाती है, वहीं केमिकल ओशनोग्राफी में समंदर में छिपे खनिज पदार्थों का पता लगाया जाता है जबकि जियोलॉजिक ओशनोग्राफी का संबंध समुद्र की गहराईयों में स्थित चटटानों और समुद्री आकृतियों के विश्लेषण से है। दूसरी ओर मरीन बायोलॉजी में समुद्री जीवों के जीवनचक्र पर नज़र रखी जाती है।

शैक्षणिक योग्यता

ओशन इंजीनियर बनने के लिए इसमें बैचलर्स डिग्री (बीई या बीटेक) होना आवश्यक है। इसके लिए पहले साइंस स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण करना होगा। इसके बाद आइआइटी-जेईई या एआइई के एंट्रेंस एग्जाम को क्लीयर करना होगा। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के इंजीनयरिंग कॉलेजों में दाख़िला लिया जा सकता है। बैचलर्स के बाद आप चाहें तो ओशनोग्राफी, मरीन जियालॉजी, मरीजन साइंसेज, ओशन साइंस, फिजिकल ओशनोग्राफी आदि पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में दाख़िला ले सकते हैं। एमटेक प्रोग्राम में एनरॉल कराने के लिए पेहले गेट (जीएटीइ) एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो सीएसआइआर-नेट परीक्षा क्वालीफाई करनी होगी।

पर्सनल स्किल्स

एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ-साथ छात्रों के भीतर लंबी समुदी यात्रा में रुचि, फिटनेस, कंप्यूटर, नॉलेज भी ज़रूरी है। इसके अलावा उनके पास क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्लियर स्पीच, राइटिंग स्किल, लीडरशिप क्वालिटी और फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए। जो छात्र मानसिक रूप से सशक्त होते हैं वे सामने आने वाले चैलेंजेज का बखूबी सामना कर पाते हैं।

अवसर

एक ओशनाग्राफार गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी में साइंटिस, इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर आदि के पद पर काम कर सकता है। वे रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल क्लाइमेट मॉनिटरिंग, एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन, मरीन ट्रांसपोर्टेशन, अंडरवाटर व्हीकल डेवलपमेंट आदि में भी अहम भूमिका निभाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंछिया, एजुकेशनल इंस्टीटयूटस, कारपोरेटस आदि में कई अवसर मिलते हैं। देश-विदेश की तेल कंपनियों में भी ओशन इंजीनियर्स की हायरिंग होती है। इसके अलावा, जिन्हें रिसर्च और टीचिंग में दिलचस्पी है, वे इस ओर क़दम बढ़ा सकते हैं। इंडिया के अलावा विदेशों में भी ओशन इंजीनियर्स और नेवल आर्किटेक्टस की काफी डिमांड है।

संस्थान

आइआइटी खड़गपुर।
www.iitgp.ac.in
आइआइटी मद्रास।
https://www..iitm.ac.in
नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालिकट।
www.nitc.ac.in/
नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा।
www.nio.org ❑❑

इस्लामी दुनिया

परमाणु वार्ता दोबारा शुरू होने पर ईरान ने दिखाया सख़्त रुख़

तेहरान : ईरान ने खत्म हुए परमाणु समझौते पर विएना में फिर से शुरू वार्ता के सिर्फ एक दिन बाद ही सख़्त अपनाया है। उसने कहा कि पहले बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उन पर दोबारा वार्ता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के सख़्त रुख से स्पष्ट हो गया कि पिछले छह दौर में हुई सभी चर्चाओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर उन पर भी बातचीत होनी चाहिए।

उइगर उत्पीड़न में जिनपिंग का भी हाथ

चीन के उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न से जुड़े लोक दस्तावेज़ों से यह पता चलता है कि इस उत्पीड़न के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शीर्ष नेताओं का हाथ है। हालांकि चीन लगातार ऐसे आरोपों से इंकार करता आ रहा है। लीक दस्तावेज़ों पर आधारित रिपोर्ट में इन नेताओं के ऐसे कई भाषण शामिल हैं, जिनमें उइगर मुसलमानों को बड़ी संख्या में क़ैद में रखने और जबरन मज़दूरी करवाने की बात सामने आई है।

करतारपुर : बिना सिर ढंगे फोटो खिंचाने पर पाक मॉडल ने मांगी माफी

लाहौर : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करतारपुर साहिब के बाहर बिना सिर ढंकी तस्वीर खिंचाने का मामला गरमाने के बाद पाकिस्तानी मॉडल सौलेहा को माफी मांगनी पड़ी हैं गुरुद्वारे के दरबार साहिब में पाकिस्तानी डिजाइनर कपड़ों के विज्ञापन की शूटिंग की सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद 'मन्नत क्लोदिंग' ने भी अपने अकाउंट पर सफाई देते हुए कहा कि उसने यह शूट नहीं कराया है।

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के दर्जनों पूर्व अफसर मार डाले

काबुल : तालिबान लड़ाकों ने अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता पर काबिज़ होने के बाद से 100 से अधिक पूर्व पुलिस और खुफिया अधिकारियों को या तो क्रूरतापूर्वक मार डाला है या जबरन ग़ायब कर दिया है। मानवाधिकारी निगरानी समूह ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। समूह ने आम माफी घोषित किए जाने के बावजूद अपदस्थ सरकार के सशस्त्र बलों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई जारी रखने का इशारा किया। तालिबान ने सरकारी रिकॉर्ड का उपयोग कर पूर्व अफसरों व आत्मसमर्पण करने वालों को निशाना बनाया।

सौर ऊर्जा
धरती बचाने की चुनौती

अतुल कनक

पिछले तीन दशकों में सारी दुनिया में जिस तरह से प्राकृतिक उथल-पुथल मची है, उसने दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को आगाह कर दिया है कि अगर हम अब भी वातावरण में ज़हरीली गैसों के उत्सर्जन को लेकर सावधान नहीं हुए, तो समूची मानवता के लिए आने वाले दिन बहुत ही कठिन होंगे। कहीं जंगल जल रहे हैं, तो कही बिन मौसम बरसात हो रही है और बाढ़ आ रही हैं, कहीं भूस्खलन जैसी आपदा देखने को मिल रही है, तो कहीं समुद्र का जल स्तर ख़तरनाक तरीक़े से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। बेहद ठंडे माने जाने वाले प्रदेशों में भी तापमान में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोत्तरी हो रही है। वैज्ञानिक इन घटनाओं का कारण ग्रीन हाउस प्रभाव को मानते हैं। ग्रीन हाऊस प्रभाव यानि वातावरण में ज़हरीली गैसों का आवश्यकता से अधिक उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग से लेकर एअर कंडीशनर, फ्रिज जैसे उपकरणों के अतिप्रचलन और कोयले से उत्पादित विद्युत पर हमारी बढ़ती निर्भरता ज़हरीली गैसों के उत्सर्जन का बड़ा कारण है। रही सही कसर उन जंगलों की कटाई ने पूरी कर दी, जो कार्बन डाइ ऑक्साइड जैसी गैसों को अवशोषित कर लिया करते थे। हालत यह है कि वैज्ञानिक अब तो इस बात तक की कल्पना करने लगे हैं कि यदि यही सब चलता रहा तो भविष्य के मानव को अपने साथ कृत्रिम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना होगा। इस कल्पना को फिजूल इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हवा साफ करने वाले उपकरण (एयर प्यूरीफायर) का कारोबार गति पकड़ चुका है।

वायुमण्डल में बढ़ते प्रदूषण ने दुनिया को चिंतित कर दिया है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में इस बात पर विमर्श बहुत प्रबल हुआ है कि मानवता को कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जाए? दुनियाभर के नीति नियंता इस या उस मंच पर पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर परस्पर विचार करते दिख रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से मानवता को बचाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक यह कि परंपरागत ईंधन स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जाए और दूसरा यह कि उन जंगलों की सुरक्षा की जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं।

वायुमण्डल में बढ़ते प्रदूषण ने दुनिया को चिंतित कर दिया है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में इस बात पर विमर्श बहुत प्रबल हुआ है कि मानवता को कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जाए? दुनियाभर के नीति नियंता इस या उस मंच पर पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर परस्पर विचार करते दिख रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से मानवता को बचाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक यह कि परंपरागत ईंधन स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जाए और दूसरा यह कि उन जंगलों की सुरक्षा की जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं।

दुनिया में शान्ति और सकारात्मकता की स्थापना तथा संरक्षा के लिए सक्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्र की पहल पर सन 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में दुनियाभर के देशों ने कार्बन उत्सर्जन पर इस तरह नियंत्रण स्थापित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी कि धीरे धीरे कॉर्बन उत्सर्जन शून्य हो जाए और पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन विसंगति यह रही कि जो देश अपने संसाधनों के दम पर इस दिशा में अन्य देशों के लिए एक मिसाल हो सकते थे, उनमें से भी कई अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति उदासीन रहे। बेशक ग़रीब देशों के लिए जो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को त्याग कर नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों की स्थापना करना इसलिए एक दुरूह कार्य हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक सीमा होती है, इसीलिए करीब एक दशक पहले विकसित देशों ने करीब एक दशक पहले यह वादा किया था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निबटने के लिए वे हर वर्ष सौ अरब डॉलर देंगे। लेकिन विकसित देशों ने न तो इस अवधि में अपने उस वादे को निभाया और न ही हाल में ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में उस प्रतिबद्ध को दोहराना ही आवश्यक समझा।

देखा जाए तो संकट ऐसे ही नहीं गहरा रहा। ज्यादातर देशों की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय हित आड़े आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे देशों ने अब तक यह घोषित नहीं किया है कि वे शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति को कब तक हासिल करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का आधार जीवाश्म ईंधन है और इसलिए वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने में उत्साह नही दिखा रहा। लेकिन रूस और आस्ट्रेलिया और भारत जैसे कुछ देशों ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त नहीं कीं। भारत उन देशों से भी अलग हो गया है जिन्होंने वनों की कटाई पर नीतिगत अंकुश लगाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

लेकिन भारत ने पहली बार कॉर्बन उत्सर्जन शून्य करने संबंधी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। शिखर सम्मेलन के अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया को जो 'पंचामृत' सूत्र दिया, उसने दुनिया को एक राह दिखाई है कि बिना प्रकृति से रिश्ता क़ायम रखे हम मानवता के सुख को संवर्द्धित नहीं कर सकेंगे। मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। इसका सीधा सा आशय यह है कि हम सूरज की ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी। हालांकि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों को सौर ऊर्जा के उपयोग के संसाधन बढ़ाने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। पनबिजली घर और परमाणु बिजली घर भी एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी विकासशील देशों और ग़रीबी देशों को बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होगी। कोरोना महामारी के तुरंब बाद इस बजट को जुटा पाना सबके बस में नहीं होगा।

परंपरागत ऊर्जा साधनों से मुक्ति पाने के लिए वैकल्पिक साधनों का एक पूरा संजाल खड़ा कर पाना भी भारत जैसे विशाल देशों के लिए कोई आसान नहीं है। मसलन बिजली से चलने वाली कारों के लिए देशभर में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन पुरानी कहावत है कि जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। भारत ने वर्ष 2070 तक अपने यहां कॉर्बन उत्सर्जन शून्य स्तर पर लाने का वादा किया है। उम्मीद की जा सकती है कि अपने कड़े फैसलों के लिए में रही भारत की मौजूदा सरकार इस दिशा में भी कुछ ठोस क़दम उठाएगी। मसलन, भारत में सन 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता का आध ा उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पनबिजली आदि से करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

हालांकि अकेले भारत की कोशिशों से सारी पृथ्वी का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो सकेगा। लेकिन भारत इस प्रसंग में दुनिया को एक राह तो दिखा ही रहा हे। वरना जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जानी मानी पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का दिया यह बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि 'यह सम्मेलन विश्व भर के नेताओं के लिए ऐसे पाखंड का मंच बन गया है, जहां वे यह दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए वो संवेदनशील हैं। वास्तव में हम उस चिंतन से बहुत दूर हैं, जो इस संबंध में ज़रूरी है।' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो यह भी कहा कि दुनिया इस समय तबाही के डिवाइस से जुड़ी है। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हमारे पास जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे संकट को हल करने के लिए क्षमता और संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हम पर्याप्त क़दम नहीं उठा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रकृति से जुड़ाव की पहल का आहवान इस स्थिति को बदल सकेगा जिसे रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने ग्लासगो में ही कहा-'हम खुद अपनी कब्रें खोदने के काम में लगे हुए हैं। हमें इसे रोकना होगा।' ❑❑

अकेले भारत की कोशिशों से सारी पृथ्वी का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो सकेगा। लेकिन भारत इस प्रसंग में दुनिया को एक राह तो दिखा ही रहा हे। वरना जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जानी मानी पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का दिया यह बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि 'यह सम्मेलन विश्व भर के नेताओं के लिए ऐसे पाखंड का मंच बन गया है, जहां वे यह दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए वो संवेदनशील हैं। वास्तव में हम उस चिंतन से बहुत दूर हैं, जो इस संबंध में ज़रूरी है।' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो यह भी कहा कि दुनिया इस समय तबाही के डिवाइस से जुड़ी है।

चुनौती बनता जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य

मनोज निगम

आज के दौर में आबादी का बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि अब बच्चे भी मानसिक समस्याओं की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कारण भले कुछ भी हों, लेकिन मानसिक समस्याओं और रोगों का तेज़ी से बढ़ना समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय तो है ही।

तीसरी लहर की आशंका के चलते देश के लगभग सभी राज्यों ने अधिकांश शैक्षणिक संस्थाओं को नियम शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है और कुछ इसकी तैयारी में है। बीते बीस महीनों में समाज ने बहुत कुछ खोयाा है तो बहुत सारे अनुभव भी लिए है, सीख भी मिली हैं। छोटे बच्चे स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन से वंचित रहे। अब जब शैक्षणिक संस्थाएं खुल रही हैं तो यह भी देखने में आ रहा है कि बच्चे, शिक्षक और परिवेश वैसा नहीं रहा, जैसा महामारी से पूर्व था। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों को अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत की देखभाल करने में सहानुभूति और सहयोग देना आज पहली ज़रूरत है।

अवसाद और खुदकुशी की लगातार बढ़ती घटनाएं हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। कहने को पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गहराते संकट को देखते हुए सरकारें जागी तो हैं, पर समस्या के दायरे को देखते हुए लगता है कि लोगों को मानसिक समस्याओं से उबारने और स्वस्थ्य रखने के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के संकट से निपटने के लिए न केवल सरकारों को बल्कि समाज को भी आगे आना होगा। इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत इसलिए भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएच ओ) पहले ही चेतावनी दे चुका हे कि कुछ ही वर्ष में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी - अवसाद की दूसरी बड़ी समस्या बन जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की दो वर्ष पहले की एक रिपोर्ट बताती है कि हर सात में से एक भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित है। कोविड-19 संक्रमण की दोनों लहरों की भयावहता के बाद ये आंकड़े और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं।

तीसरी लहर की आशंका के चलते देश के लगभग सभी राज्यों ने अधिकांश शैक्षणिक संस्थाओं को नियम शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है और कुछ इसकी तैयारी में है। बीते बीस महीनों में समाज ने बहुत कुछ खोयाा है तो बहुत सारे अनुभव भी लिए है, सीख भी मिली हैं। छोटे बच्चे स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन से वंचित रहे। अब जब शैक्षणिक संस्थाएं खुल रही हैं तो यह भी देखने में आ रहा है कि बच्चे, शिक्षक और परिवेश वैसा नहीं रहा, जैसा महामारी से पूर्व था। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों को अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत की देखभाल करने में सहानुभूति और सहयोग देना आज पहली ज़रूरत है।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर से लेकर तमाम संस्थाएं बच्चों, शिक्षकों, शैक्षिक कार्यकर्ताओं और आमजन के मानसिक स्वास्थ्य की उलझनों को दूर करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। पिछले बीस महीनों में विभिन्न मनोचिकित्सक, शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज के विभिन्न तबक़ों से बातचीत करना और उन्हें जागरुक बनाना ज़रूरी है। जब तक लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में बताया नहीं जाता, तब तक वे इससे अनजान ही रहेंगे और दिनों दिन मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में एक बड़ी बाधा तो यही है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वे किसी मानसिक व्याधि से घिरते जा रहे है। जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वे किसी चिकित्सक के पास पहुंचते हैं इसलिए आज सबसे पहली ज़रूरत मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरुक बनाने की है। साथ ही इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि इन मुश्किल हालात में उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को कैसे सहयोग किया जा सकता है, स्वयं की देखभाल कैसे की जा सकती है और मानसिक तनाव से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है।

तनाव होना और गुस्सा आना एक सहज मानवीय स्वभाव है लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। आज भारत में अवसाद के मामले जिस तेज़ी से बढ़ रहें हैं, विशेषकर से बच्चों और नौजवानों में, वे इसी का नतीजा है कि हम समय रहते मानसिक व्याधियों को जान नहीं पाते। तनाव के दौरान विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में तमाम तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ लोग चीज़े तोड़ देते हैं, तो कुछ गाली बकने लगते हैं, दरवाज़ा बंद करके रोते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो तनाव की स्थिति में संगीत सुनते हैं, बाहर घूमने निकल जाते हैं, गुनगुनाते हैं। कई अध्ययनों में सामने आया है कि महामारी के दौरान चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, घबराहट ज़्यादा होती है और कुछ नहीं नहीं कर पा सकने की स्थिति में अपराध बौध पैदा होने लगता है। यह सब महामारी के दौरान देखा गया। कोरोना महामारी को लेकर लंबे समय से जिस तरह की ख़बरें, सूचनाएं देखने और पढ़ने को मिलती रही हैं, उससे भी एक डरावना वातावरण बन गया हैं शिक्षकों में भी बच्चों में आए शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना करने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता न कर पाने को लेकर चिंता देखने को मिली। इसलिए महामारी ने सभी को सबक़ यही सिखाया है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी मानसिक सेहत को मज़बूत बनाए रखना कितनी ज़रूरी है।

देश-दुनिया में बीते बीस महीनों के दौरान लोगों ने जिस संकट का सामना किया है, उसमें आजीविका, स्वास्थ्य, भविष्य की चिंता, बुरे विचारों को हावी होना, भय के कारण नींद न आने की बीमारी, एकाग्रता की कमी, उम्मीदों का टूट जाना, भावनात्मक रूप से अस्थिरता जैसी समस्याएं प्रमुख रही हैं। इससे लोगों में तनाव और तनाव जन्य बीमारियां काफी ज़्यादा बढ़ी हैं इसलिए पहला काम बच्चों से लेकर बड़ों तक को मानसिक सेहत के प्रति जागरुक करने का होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और छोटे छोटै समूह इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कई जगहों पर ये काम हो भी रहा है। कहने को सरकारें मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता दिवस, सप्ताह जैसे आयोजन पहले भी करती आई है, लेकिन ये कागजी खानापूरी से ज़्यादा कुछ नहीं दिखते। इसलिए इसका बीड़ा समाज को स्वयं उठाने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत हैं लोगों को यह समझाना होगा कि हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कोशिश कर हालात बदलने की ताक़त तो पैदा कर सकते हैं। अगर लोग मानसिक सेहत के प्रति जागरुक हों तो ज़रा सी समस्या होने पर भी डॉक्टरी सलाह देने से हिचकेंगे नहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भीा यह कहा गया है कि जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें पौष्टिक भोजन, अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी की बात भी कही गई है। सभी स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी और उनके स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उम्मीद है कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति लागू करते समय मानसिक स्वास्थ्य के मसले पर भी सार्थक और व्यावहारिक योजना बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीवन प्रत्याशा में कमी सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी के दौर में आई है। ज़ाहिर है, मौजूदा संकट से निकलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में सरकारों से मदद बढ़ना स्वाभाविक है। ❑❑

देश-दुनिया में बीते बीस महीनों के दौरान लोगों ने जिस संकट का सामना किया है, उसमें आजीविका, स्वास्थ्य, भविष्य की चिंता, बुरे विचारों को हावी होना, भय के कारण नींद न आने की बीमारी, एकाग्रता की कमी, उम्मीदों का टूट जाना, भावनात्मक रूप से अस्थिरता जैसी समस्याएं प्रमुख रही हैं। इससे लोगों में तनाव और तनाव जन्य बीमारियां काफी ज़्यादा बढ़ी हैं इसलिए पहला काम बच्चों से लेकर बड़ों तक को मानसिक सेहत के प्रति जागरुक करने का होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और छोटे छोटै समूह इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कई जगहों पर ये काम हो भी रहा है।

ख़ास ख़बरें

छह लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी

पिछले पांच सालों में तकरीबन छह लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने नागरिकता छोड़ दी। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1,33,83,718 भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं। 2021 में गत 30 सितंबर तक 1,11,287 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है।

आस्ट्रेलियाई संसद में काम करने वाली हर तीसरी महिला यौन उत्पीड़न का शिकार

कैनबरा : आस्ट्रेलियाई संसद में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न आम बात हे। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि हर इनमें से हर तीसरी महिला का यौन उत्पीड़न हो चुका है। आस्ट्रेलिया की संसद में पेश की गई सेट द स्टैंडर्ड शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में यह सच सामने आया है। इस साल के शुरू में संसद की एक पूर्व कर्मचारी ब्रिटनी हिंगिस ने कहा था।

महारानी को हटा गणतंत्र बना बारबाडोस

ब्रिजटाउन: कैरेबियाई देश बारबाडोस ने करीब 400 वर्ष तक अंग्रेजों से औपनिवेशिक रिश्ते खत्म कर ब्रिटिश महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय को राष्ट्राध्यक्ष पद से हटा दिया है। अब यह देश एक गणतंत्र बन गया है और सांद्रा मसोन को देश की पहली राष्ट्रपति बना दिया है। लोगों ने आधी राहत को सड़कों पर जश्न मनाया। गणराज्य बनने के बाद हीरोज स्क्वायर पर देश का राष्ट्रगान बजाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स मौजूद थे। उनके सामने महारानी एलिजाबेथ का ध्वज उतारा गया।

मालदीव : शीर्ष कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की जेल की सज़ा रद्द की

माले : मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम की सज़ा को पलटते हुए 05 वर्ष जेल और 50 लाख डॉलर का जुर्माना रद्द कर दिया है। उन्हें यह सज़ा मनी लार्ड्रिंग का दोषी ठहराते हुए दो वर्ष पहले निचली अदालत ने सुनाई थी। शीर्ष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षण में सबूतों में विसंगतियां पाई गईं व साबित नहीं हुआ कि वे दोषी हैं। ज्ञात हो कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला पर मनी लॉर्ड्रिंग के आरोप लगे थे।

नबी पाक सल्ल॰ की ज़िन्दगी
नामूना-ए-आमाल

जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत की तकमील के लिए हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का चयन फरमाया और आप (सल्ल॰) की ज़ात को इस के लिए हर तरह से तैयार किया फिर आप पर तब्लीग़ रिसालत का भार डाला और क़ुरआन करीम नाज़िल करके इंसानी दुनिया को इसकी शिक्षाओं से रोशनास कराने की तल्क़ीन की। इसी तरह आप (सल्ल॰) के लिए जो साथी चयनित किए गए वह अपने आप में बड़ी महत्ता के पात्र थे इनकी ज़िन्दिगयां आप (सल्ल॰) की आदम, बईश्त और आप (सल्ल॰) पर ईमान लाने से पहले अजीब व ग़रीब विरोधाभासों का शिकार थीं, वह अमल के कोरे फिक्र व नज़र से खाली, अख़्लाकियात से आरी, बेहंगम ज़िन्दगी गुज़ारने के आदी, शराबे नाब के रसिया और हर तरह की बुराइयों के दिल दादाह थे। मगर जूं ही नबी पाक (सल्ल॰) की निगाहें रहमत इनकी ओर केन्द्रित हुई इनके ज़ाहिर व बातिन की काया पलट कर रह गयी। फिर इनकी ज़िन्दगियों में ऐसा इंक़लाब आया कि इसकी मिसाल इस दुनिया ने न तो पूर्व के लम्बे मानवीय इतिहास में कभी देखी थी और न भविष्य के दिनों में ऐसा हो पाया, वह दौर जिसमें नबी पाक (सल्ल॰) अपने असहाब के साथ इस दुनिया में मौजूद रहे, जो कुल 23 वर्ष के समय, पर आधारित है वह इंसानी इतिहास का अफज़लतरीन, बेहतरीन हैरतअंगेज़, इंक़लाबों का केन्द्र, हक़ की सरबुलंदी और बातिल की पराजय व आत्मसमर्पण का ऐसा नमूना था जिसे हर कोई देख और महसूस कर सकता था।

आप (सल्ल॰) को सहाबा की जो जमाअत मिली थी वह आप (सल्ल॰) ही की तरह चयनित थी अल्लाह ने ख़ासतौर से आपकी मुसाहबत के लिए ही उन्हें पैदा किया था, इस्लाम लाने के पहले वह बुराईयों की पोट थे मगर दामने इस्लाम से जुड़ाव के बाद वह ऐसे बदले कि खुद अच्छाईयां इन पर रश्क़ करने लगीं, शराफ़त को इनसे दवाम मिला, हक़ परस्ती को आबरू नसीब हुई, सदक़ व सफा के मोती इन्हीं के ज़रिए चमके, अख़्लास व वफा को वक़ार व ऐतबार मिला।

सहाबा की सीरत आदत, बल्कि इनकी पूरी ज़िन्दगी में जो तब्दीली हुई, इसमें एक तो खुद इलाही मसलहत का दख़ल था कि अल्लाह-तबारक तआला ऐसा ही चाहते थे चुनाँचे ऐसा ही हुआ मगर इसके साथ-साथ एक और बात यह भी थी कि इन लोगों को रसूले (सल्ल॰) खुदा जैसी मरबी, कामिल, बेलौश मोहसिन शफीक़ उस्ताद मिला। लिसान अल अस्र, अकबर इलाहाबादी ने नबी पाक (सल्ल॰) की पुर तासीर नज़र और सहाबा कराम की ज़िन्दगी में आने वाले हैरतअंगेज़ इन्क़लाब की तरफ इशारा करते हुए खूब कहा है :-

खुदा न थे जो राह पर औरों
के हादी बन गए
क्या नज़र थी जिसने मर्दों को
मसीहा कर दिया!

क़ुरआन करीम में जगह-जगह सहाबा ए रसूल के औसाफ़ बयान किए गए हैं। राहे हक़ में इनकी क़ुर्बानियों का ज़िक्र किया गया है, इनके मरतबे आलिया की वज़ाहतें की गयीं हैं और दुनिया ही में इन्हें रज़ा-ए-इलाही की खुश ख़बरियों से नवाज़ा गया है। सूरह अलफतह की एक लम्बी आयत है जिसमें सहाबा कराम की अमली विशेषताओं का ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ''मौहम्मद अल्लाह

सूरह अलफतह की एक लम्बी आयत है जिसमें सहाबा कराम की अमली विशेषताओं का ज़िक्र है , अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ''मौहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वह कुफ्फ़ार पर सख़्त और आपस में रहम दिल हैं तुम उन्हें रुकू और सज्दे में मशगूल पाओगे, वह अल्लाह के फज़्ल और उसकी सज़ा की तलब में लगे रहते हैं।

के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वह कुफ्फ़ार पर सख़्त और आपस में रहम दिल हैं तुम उन्हें रुकू और सज्दे में मशगूल पाओगे, वह अल्लाह के फज़्ल और उसकी सज़ा की तलब में लगे रहते हैं।

इनकी निशानियां (शनाख़्त नामे) इनकी पेशानियों पर हैं सज्दों की वजह से। यही इनकी सिफ्त तौरयत में भी बयान की गयी) है और इन्जील में इनकी मिसाल यूँ दी गयी है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको तकवीयत दी, फिर इसमें और मज़बूती आयी, फिर वह अपने तने पर खड़ी हो गयी ताकि कुफ्फ़ार इनके फलने-फूलने पर जलें। इनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया इनके लिए अल्लाह ने मग़फरत और अज्र अज़ीम का वादा किया है।''

सहाबा कराम की ज़िन्दगियों की नक्शाकशी इससे ज़्यादा जामेअ अंदाज़ में नही हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हर खसूसियत को इस आयत में खोल कर रख दिया है, यूं तो इनकी यही विशेषता सबसे बड़ी थी कि उन्होंने अल्लाह के महबूब नबी (सल्ल॰) को देखा इनकी जनाब में बारयाबी का शर्फ हासिल किया था मगर इनके साथ मिलकर इलाह हक़ के रास्ते में उन्होंने जिस जाँ सुपारी के साथ क़ुर्बानियां पेश कीं इसने उन्हें अल्लाह के नबी (सल्ल॰) की निगाह में और अल्लाह तबारक व तआला के यहां भी बड़ा सर बुलंदियों का पात्र बना दिया, इनमें से हर एक के दिल में अपने नबी (सल्ल॰) अल्लाह तबारक व तआला और अपने दीने-मतीन की ऐसी मोहब्बत जाग गयी थीं कि वह इस राह में अपना सब कुछ क़ुर्बान करने को हर वक़्त तैयार रहते थे। यही वजह है कि आप (सल्ल॰) ने भी विभिन्न मौक़ों पर अपने सहाबा की अज़मत को बयान फरमाया और उम्मत को तलक़ीन की कि वह न सिर्फ इनकी ताज़ीम व तकरीम को अपना दीनी व ईमानी फरीज़ा समझे बल्कि इनकी ज़िन्दगी और सीरत व किरदार को अपनाते हुए ज़िन्दगी भी गुज़ारें। आपने एक अवसर पर इर्शाद फरमाया 'मेरे सहाबा को गालियां न देना, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान हैं अगर तुम में से कोई व्यक्ति ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे। (अल्लाह के रास्ते में) तो इनमें से किसी एक के खर्च किए हुए मद (मामूली मिक़दार) के बराबर भी नहीं पहुंच सकता (सही-मुस्लिम, किताब अल फज़ाइल)।

इस हदीस पाक से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम में सहाबा कराम की अज़मत कितनी अधिक है और अल्लाह के रास्ते में इनकी दी गयी क़ुर्बानियों की क़द्र व क़ीमत किस क़दर आला है। इसी तरह एक और हदीस में जो बहुत ही मशहूर हैं और जुमे में खुत्बे के दौरान इमाम साहब उसे पढ़ते हैं, आप (सल्ल॰) ने क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत को सावधान करते हुए फरमाया ''मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, जिसने इनसे मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़ज़ रखा इसने मुझसे बुग्ज़ रखा और बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं फिर जो उनके बाद आने वाले हैं।'' इस हदीस से भी सहाबा कराम की बेपनाह अज़मत का इज़हार होता है कि नबी पाक (सल्ल॰) इन से मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की अलामत क़रार दे रहे हैं और इनसे बुग्ज़ को अपनी ज़ात से बुगज़ की अलामत क़रार दे रहे हैं।

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल अस्र नं॰ 103)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें तीन आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

क़सम है अस्र (युग) की।

अस्र ज़माने (युग) को कहते हैं अर्थात् क़सम है ज़माने की जिसमें इंसान की उम्र भी दाख़िल है जिसे कमाल और अच्छाई प्राप्त करने की बहुमूल्य वस्तु समझना चाहिए या क़सम है अस्र की नमाज़ के वक़्त की, जो दुनिया के कारोबार में तल्लीनता और धार्मिक आधार पर बहुत बड़ाई का समय है (यहां तक हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ ने हदीस में कहा है कि जिसकी अस्र की नमाज़ छूट गई हो ऐसा समझो कि उसको सब घर बार लुट गया) या कसम है हमारे रसूल के कल्याणकारी समय की जिसमें उनके रसूल होने का और उनके पश्चात् ख़िलाफ़त का प्रकाश बड़ी आबोताब से चमका।

कि नि:संदेह इंसान टोटे में है।

इससे बढ़कर टोटा क्या होगा कि बर्फ बेचने वाले दुकानदार की भांति उसके व्यापार का मूलधन जिसे उम्र कहते हैं क्षण-क्षण कम होता जा रहा है। अगर इस भागते समय में कोई ऐसा काम न किया जिससे यह चलती आयु ठिकाने लग जाये बल्कि सदैव रहने वाली बहुमूल्य वस्तु बनकर सदैव के लिए उपयोगी बन जाये तो फिर टोटे की कोई सीमा नहीं। ज़माने का इतिहास पढ़ जाओ और स्वयं अपनी ज़िन्दगी की घटनाओं पर विचार करो तो तनिक सा भी विचार करने से सिद्ध हो जायेगा कि जिन लोगों ने परिणाम को देखकर काम न लिया और भविष्य से उदासीन रहकर केवल सांसारिक आनन्दों में समय ख़राब किया वे अंतत: असफल व नामुराद बल्कि तबाह व बर्बाद होकर रहे। आदमी को चाहिए कि वक़्त की क़दर पहचाने और यूं ही आयु के क्षणों को ग़फ़लत और शरारत और खेल कूद में न बिताये। जो समय उन्नति और महानता प्राप्त करने के लिए है, विशेष रूप से वह समय जिसमें रिसालत का सूर्य सर्वोच्च शिखर से संसार को प्रकाशित कर रहा है, अगर ग़फ़लत और भूल में व्यतीत कर दिया गया तो समझो कि इससे बढ़कर आदमी के लिए कोई टोटे की बात नहीं हो सकती। बस सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है जो इस नाशवान आयु को बाक़ी रखने और बेकार जीवन को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करते हैं और अच्छे समय को और अवसरों को ग़नीमत समझकर सौभाग्य और कमाल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यह वही लोग हैं जिनका वर्णन अगली आयत में आ रहा है।

रुकू नं॰ 1

उन लोगों के अतिरिक्त जो ईमान लाये और भले काम किये और आपस में सच्चे दीन की ताक़ीद करते रहे और आपस में संतोष की ताकीद करते रहे।

अर्थात् इंसान को टोटे से बचने के लिए चार बातों की आवश्यकता है, प्रथम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाये और उनकी हिदायतों और वादों पर चाहे दुनिया से संबंधित हों या आख़िरत से, पूरा यकीन रखे। नंबर दो - इस विश्वास का प्रभाव केवल दिल दिमाग़ तक ही सीमित न रखे बल्कि शारीरिक अंगों से भी उसका प्रदर्शन करे, जिससे उसका व्यावहारिक जीवन ईमान का आइना हो। तीसरी बात - केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति और सुधार के संबंध में ही न सोचे बल्कि राष्ट्र और समाज के लाभ को सम्मुख रखे। जब दो मुसलमान मिलें एक दूसरे को अपनी कथनी और करनी से सच्चे दीन और प्रत्येक मामले में सच्चाई को पकड़े रहने की ताक़ीद करते रहें। चौथी बात यह है कि प्रत्येक को दूसरे का यह उपदेश और आदेश रहे कि सच्चाई के मामले में और व्यक्तिगत व सामाजिक सुधार के रास्ते में जितनी भी सख़्तियाँ और परेशानियां सामने आयें या स्वभाव के विपरीत धैर्य रखना पड़े तो पूरे सब्र (संतोष) और दृढ़ता से धैर्य रखें, ज़रा भी नेकी के रास्ते से क़दम डगमगाने न पाये जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन चार गुणों को अपनायें होंगे और स्वयं पूर्ण होकर दूसरों को पूर्ण करेंगे, उनका नाम संसार में सदा अमर रहेगा और जो निशानात छोड़कर दुनिया से जायेंगे तो वे अच्छे काम सदैव रहेंगे। उनका बदला बराबर मिलता रहेगा, वास्तव में यह छोटी सी सूरा पूरे दीन और तात्विकता का सारांश है। इमाम शाफी ने सच कहा है कि यदि क़ुरआन में से केवल यही सूरा उतार दी जाती (समझदार बंदों के लिये) हिदायत के लिये काफी थी। हमारे धार्मिक पूर्वजों में जब दो मुसलमान आपस में मिलते थे अलग होने से पहले एक दूसरे को यह सूरा सुनाया करते थे।

राकेश कपूर

उत्तर प्रदेश की तस्वीर में उभरते नये किरदार

अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों में लगभग चार माह का समय शेष है मगर सभी प्रमुख राजनैतिक दलों ने अपनी-अपनी शतरंजी चौसर बिछाना शुरू कर दी है। वैसे एक मायने में ये चुनाव पिछले सभी चुनावों से हटकर होने वाले हैं क्योंकि प्रारंभिक ज़मीनी सर्वेक्षणों के बाद किसी भी पार्टी की हवा चलने की संभावना नहीं है। बल्कि इसके विपरीत हालात इतने उलझे हुए हैं कि हर पार्टी स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। इसकी असली वजह यह है लगभग हर पार्टी के वोट बैंक में ऐसे छेद हो गये हैं कि जिन्हें भरने का काम केवल मतदाता ही अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं? इस बार के चुनावों में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी की शीर्षस्थ नेता सुश्री मायावती का यह अन्तिम चुनाव हो सकता है। मगर उनका दलित खास कर रैदासी वोट बैंक इस प्रकार नहीं बिखरा है कि वह अपना मत तितर बिर होकर दे। हालांकि युवा दलित नेता चन्द्रशेखर 'रावण' इस वोट बैंक को पाने में ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं मगर उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके साथ समाज के अन्य वर्ग किसी तरह जुड़ पाते हैं, ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोग।

इस बार के चुनावों में एक नया खिलाड़ी दल 'इत्तेहादे मुसलीमीन' भी है जिसके नेता असउद्दीन ओवैसे हैं। ये अपना सारा दारोमदार मुस्लिम वोट बैंक पर रखे रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान मतदाता बहुत होशिया समझे जाते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते हैं। नि:संदेह इस वर्ग का लक्ष्य शुरू से ही जनसंघ या भाजपा को परास्त करना रहा है परंतु इन्होंने कभी भी किसी मुस्लिम नेता के हाथ में अपना चुनावी भाग्य नहीं दिया और हमेशा ऐसे हिन्दू नेता की सरपरस्ती कबूल की जो उन्हें राष्ट्रधारा में समाहित रख सके।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1969 के राज्य के वे मध्यावधि चुनाव हैं जब चन्द्रभानु गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त होने लगा था। उस समय लखनऊ के मशहूर चिकित्सक स्व. डॉ0 जे.जेड. ए. फरीदी के नेतृत्व में 'मुस्लिम मजलिस' पार्टी का गठन हो चुका था। उन चुनावों में डॉ. फरीदी ने स्व. चौधरी चरण सिंह के नवगठित 'भारतीय क्रांति दल' के साथ चुनावी गठबंधन किया था और राज्य के मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने चौधरी साहब को अपना नेता मान लिया था परंतु पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाताओं का अधिसंख्य भाग कांग्रेस के साथ ही रहा था। मुस्लिम मजलिस को इन चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी।

1974 में कांग्रेस नेता स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा ने इस समीकरण को मुस्लिमों में अपनी लोकप्रियता के बूते पर तोड़ डाला था लेकिन अन्त में स्व. बहुगुणा कांग्रेस छोड़ कर चौधरी साहब की पार्टी में आ गए। मगर आगामी चुनावों में ओवैसी सीध मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डालने की जो शतरंज बिछा रहे हैं उसमें उनकी सफलता पर इस राज्य के आम मुसलमानों को ही संदेह है और वे मानने लगे हैं कि ओवैसी को वोट देने से भाजपा की ताक़त में बढ़ोत्तरी होगी।

दूसरी ओर मायावती से मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास उठ चुका है और वे मानने लगे हैं कि उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इस माहौल में दलित व मुस्लिम दोनों ही मतदाता फिलहाल बहुत बड़े भ्रम में हैं कि वे जायें तो जायें किधर क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरह जिन्ना आदि नेताओं की याद दिला कर उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मतों का तेज़ी के साथ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है। अखिलेश के इस बयान से उनके कट्टर समर्थक समझे जाने वाले पिछड़े वर्ग के मतदाता भी खासे नाराज़ बताये जाते हैं। इस राज्य की हक़ीक़त यह है कि पुलिस से लेकर सुरक्षा बलों में इसी वर्ग के लोग अधिसंख्य रूप से शामिल होते हैं। मगर ओवैसी आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को विचलित कर रहे हैं और इस पार्टी को भीतरखाने भाजपा का मित्र बता रहे हैं। यह भी निश्चित है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की कमान श्रीमति प्रियंका गांधी ने संभाली है, सड़कों पर वह ही प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही हैं।

प्रियंका गांधी ने राज्य की महिला मतदाताओं को जाति-धर्म से ऊपर उठकर अपना वोट बैंक बनाने का जो प्रयास किया है उसके चुनावों में हमें कुछ आश्चर्यजनिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल उनके इन प्रयासों को बहुत हल्के में लिया जा रहा है मगर यह हक़ीक़त है कि वह स्व. इंदिरा गांधी की पोती हैं। राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इंदिरा गांधी को स्त्री शक्ति का महान प्रतीक आज भी माना जाता है। अत: प्रियंका अपनी हर जनसभा में इंदिरा जी का नाम याद दिलाना नहीं भूलतीं। इसके साथ ही हाथरस की दुखद घटना से लेकर लखीमपुर खीरी के किसान हत्याकांड तक प्रियंका गांधी ने जिस दिलेरी से सत्ता की मुख़ालफत की उसका संज्ञान भी उत्तर प्रदेश की आम जनता ने लिया है। विशेष रूप से प्रियंका द्वारा किये गये इस नारे 'लड़की हूं-लड़ सकती हूं' को पार्टी की राज्य इकाई जिस तरह चुनावी

बाक़ी पेज 11 पर

क्या क्षत्रपों के राष्ट्रीय नेता बनने के मंसूबे सफल हो सकेंगे?

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसी हलचलें भी हैं, जिनके दूरगामी संदेशों को या तो देखने की कोशिश नहीं हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी विरोध से उपजे राजनीतिक घटाटोप में उन पर साफ निगाह पड़ ही नहीं रही है। इन दिनों तीन क्षेत्रीय दल ऐसे हैं, जिनकी महत्वकांक्षा छुपाए नहीं छुप रही है। अपने क्षेत्र या राज्य की सीमाओं के बाहर सफल राजनीतिक कुलांचे भरने के लिए वे लगातार कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी जिस तरह राजनीतिक दांव चल रही है, उसके संदेश स्पष्ट है।

राष्ट्रीय इतिहास के कठोर पत्थर पर अपना नाम खुदवाने की ममता बनर्जी की कोशिश नई भले ही हो लेकिन शरद पवार अरसे से ऐसी कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री पद की अपनी आकांक्षा को वे शाब्दिक जाल और राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के माध्यम से हर मुमकिन मौक़े पर ज़ाहिर करते रहे हैं।

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जनता दल (यू॰) नेता नीतीश कुमार तो मोदी विरोधी विपक्षी खेमे के प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर उभर भी चुके थे। लेकिन बाद में बिहार की सरकार को सहयोगी लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी लालटेन की रोशनी में राह दिखाना तेज़ किया तो नीतीश ने राष्ट्रीय इतिहास रचने के अपने सपने को कुछ सालों के लिए मुल्तवी कर दिया।

बेशक वे भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनकी भी महत्वकांक्षा छुपी हुई नहीं है। तीनों नेताओं ने यह समझ लिया है कि राष्ट्रीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपनाम नाम दर्ज करना तब ज़्यादा आसान होगा जब उनके दल क्षेत्रयीता की सीमाओं को पार करके अपना राज्यस्तरीय दर्जा पीछे छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके पास अगर पचास लोकसभा सांसद भी होंगे तो देश के नेतृत्व पर उनके लिए दावेदारी आसान होगी, बशर्ते कि भाजपा को अगले आम चुनावों में बहुमत न मिले।

कोलकाता की रायटर्स बिल्डिंग पर तीसरी बार कब्ज़ा करने के बाद

बाक़ी पेज 11 पर

दिल्ली दंगा - पिता पुत्र पर चलेगा मस्जिद जलाने का केस

अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान एक मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर आग लगाने, तोड़फोड़ और पथराव करने के मामले में पिता पुत्र के ख़िलाफ़ अभियोग तय कर दिए। अदालत ने कहा कि दोनों के ख़िलाफ़ आगज़नी और दंगा करने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी ख़ास इलाके में धार्मिक नारे लगाने वाली और मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने वाली हिंसक भीड़ में आरोपी मिथन सिंह और उनके बेटे जॉनी कुमार शामिल थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट के पूछने पर दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। अदालत ने उनका तर्क सुनने के बाद अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया हैं। अदालत ने आरोपियों के ख़िलाफ़ दंगा करने, घातक हथियार का प्रयोग, ग़ैरकानूनी रूप से एकत्रित होने, आगज़नी, विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग, जबरन घर में घुसने के आरोप में मुक़दमा चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष के उस तर्क को ख़ारिज कर दिया कि उनके मुवक्किलों को फर्जी मामले में फंसाया गया है और उन्हें आरोपमुक्त किया जाए। बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि घटना रिपोर्टिंग और गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई है।

अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी जानबूझकर नहीं की गई थी और दंगें के दौरान व बाद में क्षेत्र में मौजूद स्थिति के कारण हुई थी। दंगों के बाद भी कई दिन तक इलाके में आतंक और आघात का माहौल बना रहा। ऐसे में एक सप्ताह गवाहों के बयान दर्ज करने संबंधी पुलिस का तर्क संतोषजनक है।

शिकायकर्ता इसराफिल के अनुसार, मिथुन सिंह और उनके बेटे जॉनी कुमार उस हिंसक भीड़ का हिस्सा थे, जिसने 25 फरवरी 2020 को उनके घर के पास धार्मिक नारे लगाए और आग लगा दी। इससे शिकायकर्ता को अपनी जान बचाने के लिए फातिमा मस्जिद पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीड़ ने फिर मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर दिया और आग लगा दी। आरोप है कि मिथन सिंह ने अपने बेटे को मस्जिद में एक छोटा गैस सिलेंडर फेंकने का भी आहवान किया। विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि इन गवाहों के स्पष्ट बयानों को देखते हुए जो दोनों आरोपियों को अच्छी तरह से जानते थे और वे सभी एक ही पड़ोस में रहते थे, से स्पष्ट है कि दोनों आरोपियों ने बर्बरता, पथराव और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को जलाने का सहारा लिया था।

टीम को मुश्किलों से पार पाने की क्षमता है द्रविड़ में

मनोज चतुर्वेदी

टी-20 विश्व में टीम इंडिया के ख़राब प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड के साथ टी-20 सीरीज़ को जीत कर ये स्पष्ट हो गया कि टीम इंडिया को मुश्किलों से निकालने में राहुल द्रविड़ पूरी तरह सक्षम है। हालांकि इससे इतर पहला टेस्ट जीत की दहलीज़ पर पहुंच कर जीत से दूर हो गया। 'द वॉल' कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बनाकर सौंपी गई उन पर जिम्मेदारी उन्होंने सही साबित कर दिखाया। रवि शास्त्री के 2017 में मुख्य कोच बनने के बाद से इस बार के टी-20 विश्व कप तक टीम इंडिया ने ढेरों सफलताएं हासिल कीं, लेकिन एक कसर रह गई। वह है आईसीसी ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाना। द्रविड़ के ज़िम्मेदारी संभालते ही पहली परीक्षा देने की बारी भी आ गई है। टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ टी-20 सीरीज जीत के साथ आगाज किया है। इस सीरीज पर द्रविड़ की छाप दिखी है। इसके अलावा हम क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप की वह सीरीज जीते है तो पिछले दिनों विश्व कप में इस टीम के हाथों मिली हार की भरपाई तो हो चुकी है अब आगे बढ़ना है।

पिछले दिनों समाप्त हुए टी-20 विश्व कप के बाद विराट कोहली के इस प्रारूप की कप्तानी छोड़ने पर रोहित शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहित यदि सफलतापूर्वक कप्तानी की शुरुआत करते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें वनडे टीम की कप्तान बनाने का दबाव बन सकता है। वैसे भी विश्व में जिन देशों में कप्तानी बंटी हुई है, वहां सफेद गेंद और लाल गेंद के अलग-अलग कप्तान हैं। इसका मतलब है कि एक कप्तान के हवाले टी-20 और वनडे टीम तो दूसरे कप्तान के हवाले टेस्ट टीम रहती है। अगर अपने यहां भी ऐसी स्थिति बनती है तो द्रविड़ की प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी यह सुनिश्चित करना कि टीम दो खेमों में न बंट जाए।

भारत में दो कप्तानों वाली स्थिति कोई पहली बार नहीं बन रही है। महेन्द्र सिंह धोनी के टैस्ट से संन्यास लेने के बाद वह और विराट कप्तान थे। लेकिन इन दोनों जैसे अच्छे संबंध रोहित और विराट में नहीं माने जाते हैं। द्रविड़ इन दोनों खिलाड़ियों के साथ खेले भी हैं और आईपीएल में कप्तानी भी की है, इसलिए दोनों को टैकल करने में उन्हें शायद ज़्यादा दिक्क़त न हो। वहीं रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर टीम को क्या दिशा देते हैं, इस पर भी टीम इंडिया का भविष्य काफी कुछ निर्भर करेगा।

रवि शास्त्री इस मलाल के साथ चले गए कि 2017 में टीम के मुख्य कोच की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद

भारतीय कप्तान विराट कोहली 33 वर्ष के हैं और टी-20 के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा 34 वर्ष के। इनके अभी चार-पांच वर्ष और खेलने की उम्मीद की जा रही है इसलिए द्रविड़ के सामने भविष्य का कप्तान तैयार करने की चुनौती भी होगी। इसके लिए उनके पास के.एल. राहुल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं।

टीम इंडिया को कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिता सके। उनके कार्यकाल में भारत के सामने तीन अवसर आए - 2019 में वनडे विश्व कप, 2021 में विश्व टैस्ट चैम्पियनशिप और फिर टी-20 विश्वकप। दो बार न्यूजीलैंड ने सपना तोड़ा तो तीसरी बार हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। द्रविड़ को भारत में 2023 में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप तक के लिए कोच की ज़िम्मेदारी सौंपी गई हैं इस दौरान ही विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप होनी है और अगले वर्ष यानि 2022 में आस्ट्रेलिया में टी-20 विश्व कप का आयोजन होना है। इसका मतलब है कि द्रविड़ को पहली बड़ी परीक्षा के लिए मात्र 10 माह ही शेष हैं। रवि शास्त्री के कोच रहते भारत ने आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके घर में दो बार टेस्ट सीरीज जीती। अन्य देशों के ख़िलाफ़ भी ढेरों सफलताएं हासिल कीं। लेकिन वह तो काम नहीं कर पाए, उसे द्रविड़ किस तरह अंजाम देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। द्रविड़ के निर्देशन में भारतीय टीम यदि तीन में से एक भी विजेता बन सकी, तो उनका लोहा एक बार फिर मान लिया जाएगा। द्रविड़ के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी काम को व्यक्तिगत रूप से करने के बजाय उसके लिए एक सिस्टम बनाना पसंद करते हैं। बतौर खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी दूसरी पारी की सफलता का यही मंत्र भी है।

हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट ने पिछले कुछ दशकों में नई ऊंचाईयों को छुआ है लेकिन एक ऐसा देश है, जिसमें जाकर भारत ने अब तक टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है और वह है दक्षिण अफ्रीका। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की हालिया सीरीज़ के बाद दक्षिण अफ्रीका का दौरा प्रस्तावित है। इस देश के ख़िलाफ़ भारत ने उसके घर में पहली टेस्ट सफलता 2006 में जोहानिसबर्ग में हासिल की थी। तब टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ही थे। इस बार वह अपनी टीम से कैसा प्रदर्शन करवा पाते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी।

बतौर खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राहुल द्रविड़ ने 2015 में अंडर-19 और इंडिया ए टीमों के कोच के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने इन चार सालों में तमाम युवाओं के कैरियर को संभाला ही नहीं बल्कि नई ऊंचाईयां भी दीं। इस दौर में उन्होंने ऐसी सप्लाई चेन बना दी थी। जैसी किसी अन्य देश में कभी नज़र नहीं आई। इसी

बाक़ी पेज 11 पर

हर आयु वर्ग की खुराक भी एक्ट्रा होती है

आयु के अनुसार हमारे बदन को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने दिनचर्या में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन और कैलोरी ले, जितनी कि हमारी आयु के अनुसार हमें चाहिए। विशेषकर औरतों को पोषक तत्वों की पर्याप्त आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनके शरीर को अधिक बदलाव से गुज़रना पड़ता है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रेगनेंसी से लेकर वृद्धावस्था। उम्र के साथ पीरियड्स, डिलीवरी और मेनोपॉज के कारण महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। अगर इसके लिए वे तैयार नहीं रहती हैं तो उन्हें एनीमिया, हड्डियों का कमज़ोर होना और ऑस्ट्रियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के होने का खतरा होता हैं यही कारण है कि महिलाओं को आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन-डी, और विटामिन बी9 (फोलेट) जैसे पोषक तत्वों को अपने खानपान में अधिक से अधिक शामिल करने की आवश्यकता होती है।

बचपन हो प्रोटीन से भरपूर! 7 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीज़े, जैसे - फल, नट्स, आलू, हरी बीन्स, ब्रोकली, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, बाजरा और राजमा को शामिल करें। उन्हें दही, पनीर, अंडा, मांस मच्छली आदि का सेवन भी कराएं। चूंकि बचपन में ही हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती और विकसित होती हैं, इसलिए उस आयु में प्रोटीनयुक्त खाना, कॉम्पलेक्स कार्बोहाइड्रेट, नट्स, कैल्शियम और आयरन से भरपूर भोजन देना चाहिए। ब्लूबेरी, दही, अखरोट आदि का सेवन भी नियमित रूप से अवश्य कराएं।

अगर आपकी बच्ची 13 से 18 वर्ष के बीच है तो जब लड़की बाल्यावस्था से किशोरावस्था की आयु में प्रवेश करती है, तो वह बायोलॉजिकल और सोशियो-इमोशनल डेवलपमेंट से होकर गुज़रती है। उस समय लड़कियों में हॉर्मोनल चेंज एक सीरीज में होता है। उस समय अगर उन्हें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उनमें कम वजन और माइक्रोन्यूट्रिएंस की कमी हो जाती है इसलिए उनको प्रोटीन के रूप में अपने खानपान में मछली, अंडे, डेयरी प्रॉडक्ट, जैसे - दूध, दही, पनीर और दालों का नियमित उपयोग करना चाहिए।

18 से 29 वर्ष, इस आयु में डाइट में ज़्यादा कैल्शियम, फोलेट और आयरन को शामिल करना चाहिए। कैल्शियम हड्डियों को मज़बूत बनाने के साथ जोड़ों से जुड़ी बीमारियों से बचाता है। फोलेट डीएनए को रिपेयर करने में मदद करता है, जो प्रेग्नेंसी होने पर बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आयरन की पर्याप्त मात्रा शरीर में हो तो इससे मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट मिलता है और टिशू रिपेयर करने में मदद मिलती है। इन तत्वों को आहार का हिस्सा बनाने के लिए दूध, दही, चीज, सोया, दाल, ब्लैक बीन्स, बीन्स, मूंगफली, पालक का नियमित सेवन करना चाहिए।

30 से 39 की आयु में मसल्स लॉस होने लगते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। अगर व्यक्ति युवावस्था की तरह पर्याप्त कैलोरी लेता रहे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और वजन बढ़ने लगेगा। मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा इस आयु वर्ग के लोगों को ब्लड प्रेशर और शुकर को संतुलित रखने के साथ शरीर को मज़बूती देती है। मैग्नीशियम के लिए बादाम, पालक, काजू और दही को सेवन करना चाहिए। 49 से 49 में विटामिन सी, ई और एंटी-ऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों को इस आयु वर्ग के लोग आहार क हिस्सा बनाएं। ये तीनों शरीर से फ्री-रैडिकल को दूर करने में मदद करते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इन विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट फूड के लिए हरी व लाल मिर्च, खट्टे फल, ब्रोकली, स्प्राउट्स, पनीर बटर, टमाटर, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लॉवर ऑयर, बादाम, गाजर, हरी सब्जियों आदि का प्रयोग करना लाभदायक होगा।

अगर आप 50 से 59 में हैं तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी और बी12 ज़रूर लें। कैल्यियम पर्याप्त मात्रा में लेते रहने के साथ ही विटामिन डी का आहार भी ज़रूरी है, ताकि कैल्शियम को हड्डियां ग्रहण कर सकें। विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स, नर्व्स और डीएनए को बनाने पर रिपेयर करने में मदद करता है। इनके लिए चिकन, मछली, लो-फैट मिल्क, दही, चीज आदि को आहार का हिस्सा अवश्य बनाएं।

60 वर्ष की आयु वृद्धावस्था के आरंभ की मानी जाती है, इस आयु में संयमित खानपान की ज़रूरत होती है, हालांकि ज़रूरी पोषक तत्वों को नियमित रूप से लेते रहना ज़रूरी होता है। इस समय प्रोटीनयुक्त आहार - बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रॉडक्टस, दूध, अंडे, टोफू खाएं। यह भी ध्यान रखें कि एक ही बार पेट भरकर खाना न खाएं, थोड़े-थोड़े अंतराल में कुछ न कुछ ज़रूरी खाते रहें।

शेष.... पाकिस्तान में न्यायपालिका...

कितना उचित है। अंग्रेजी *दैनिक डॉन* अपने संपादकीय में कहता है, 'इसे अवमानना के मामले के रूप में देखने के बजाय क्या न्याय पालिका को आरोपों के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, चाहे यह तथ्य हो या कल्पना?'

पाकिस्तान के पत्रकार सालों से अपहरण, क़ैद से लेकर नौकरी छूटने और हमले व हिंसा की धमकियां झेलते रहे हें। यह कब समझा जाएगा कि ऐसी तानाशाही बीते युग के अवशेष हैं और 21वीं सदी में उनकी कोई जगह नहीं है? मीडिया की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न तरह के कानूनी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या अवमानना क़ानून। जबकि कई देशों में ऐसे क़ानूनों को खत्म कर दिया गया है।❑❑

शेष.... उत्तर प्रदेश की तस्वीर...

माहौल में तैरा रही है उससे महिला मतदाताओं को आकृष्ट होने से नहीं रोका जा सकता परंतु यह तस्वीर काा एक पहलू है क्योंकि राज्य की 80 प्रतिशत के करीब जनता गांवों व कस्बों में निवास करती है और इस क्षेत्र की महिलाएं अपने घर के पुरुषों की मर्ज़ी पर ही मतदान करती हैं हालांकि सूचना टेक्नोलॉजी के इस दौर में गांवों में भी सामाजिक परिवर्तन आ रहा है परन्तु स्थिति अभी पूर्ण परिवर्तन की नहीं बनी है

इसके साथ ही प्रियंका गांधी की नज़र दलित व मुस्लिम दोनों ही वर्गों के मतदाताओं पर है। पिछले सालों के दौरान शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां किसी महिला, दलित या मुस्लिम पर हुए अत्याचार की घटना के बाद प्रियंका गांधी स्वयं वहां न गई हों और पीड़ित परिवार को सांत्वना न दी हो। इसके बावजूद आम मतदाताओं में यह विश्वास नहीं जग रहा है कि कांग्रेस अपने बूते पर राज्य के विधानसभा चुनावों में कोई कमाल कर सकती है। मगर कांग्रेस का यह नारा भी कम असरदार नहीं कि 'प्रियंका का संकल्प- कांग्रेस ही विकल्प' इसकी एक वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अपने से हिन्दू मतदाताओं में डर का वातावरण कानून व्यवस्था की हालत खराब होने की आशंका से बन जाता है। मगर राज्य की सत्तारुढ़ भाजपा योगी सरकार इन सभी आशंकाओं से ऊपर नज़र आती हैं और भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के आगे समूचे विपक्ष का कोई तीर नहीं चलेगा। पिछले 2017 के चुनावों में भाजपा को तीन चौथाई से अधिक बहुत मिला था और दलित व पिछड़े वर्ग के वोट भी इसे जमकर पड़े थे। इन चुनावों में ज़मीनी हक़ीक़त बेशक दूसरी नज़र आ रही है मगर इसके बावजूद पार्टी को अपनी सरकार बनने का पूरा विश्वास है क्योंकि भाजपा के अलावा किसी अन्य दल का पूरे उत्तर प्रदेश में मज़बूत संगठन नहीं है। इसके साथ जिस प्रकार विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व निर्माण को केन्द्र में लाकर भाजपा चुनावी एजेंडा तय करना चाहती है उसका तोड़ विपक्ष को फिलहाल सूझ नहीं रहा है।

विपक्षी सांसदों में इस मुद्दे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि 17वीं लोकसभा को गठित हुए ढाई वर्ष से ऊपर हो जाने के बावजूद अभी तक लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कराया गया है। संसद के इतिहास में यह पहला मौक़ा है कि उपाध्यक्ष का पद इतने लम्बे समय से ख़ाली पड़ा हुआ है। यह संवैधानिक पद है जिसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष की मर्ज़ी से किया जाता है। इस पद का चुनाव संसदीय प्रणाली में संभावित आकस्मिकताओं की नज़र से भी करना ज़रूरी होता है पारंपरिक रूप से उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दलों को दिया जाता है जिससे संसद की कार्यवाही निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चलती रहे। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष की तरह ही होता है। इस मामले में कोई समयावधि निश्चित नहीं है केवल इतना लिखा हुआ है कि नई लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाएगा।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

बढ़ने के कारण है, महामारी से अभिभावकों की आर्थिक मुश्किलें और सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मुफ्त सुविधाएं। जैसे, महामारी की पहली लहर के दौरान गांव लौटे श्रमिकों के बच्चों को न केवल सरकारी स्कूलों में आसानी से प्रवेश मिला, बल्कि यूनिफार्म, बैग, जूते आदि खरीदने के लिए उनके अभिभावकों के खाते में पैसे भी भेजे गए। रिपोर्ट बताती है कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण पढ़ाई में जो व्यवधान पैदा हुआ, इस कारण छात्रों में टयूशन पढ़ने का चलन भी बढ़ा है। कोविड से पहले ग्रामीण भारत में टयूशन पढ़ने वाले छात्र 30 प्रतिशत से भी कम थे, जो इस वर्ष बढ़कर 39.2 प्रतिशत हो गए। इस रिपोर्ट में चिंतित करने वाली दो बातें भी कहीं गई हैं एक तो यही कि स्कूलों में नामांकन बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई के मोर्चे पर जो क्षति हुई, उसकी भरपाई मुश्किल है और दूसरा यह कि ग्रामीण भारत में स्मार्टफोनों की संख्या भले ही दोगुनी हो गई है, पर स्कूली बच्चों और उसमें भी निचली कक्षा के छात्रों तक इसकी पहुंच अब भी कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है, जहां के बच्चों की स्मार्टफोन तक पहुंच सबसे कम है। ज़ाहिर है, इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त कमियां दूर की जाएं, तो परिदृश्य और बेहतर हो सकता है।❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

ने अंग्रेजों को यह साफतौर पर समझा दिया कि उनका यहां और अधिक समय तक रुकना असंभव हो गया है। उन्होंने अब समझौतों का रास्ता अपनाया। सी.आर. प्लान और वियूल प्लान (शिमला समझौता) इस ओर उठाये गये नाकाम क़दम थे।

मार्च 1946 में ब्रिटिश की नई बनने वाली सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, उस मिशन का मक़सद कौमी सरकार के गठन के लिए बातचीत करना, बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस का मानना या बंटवारा अगर ज़रूरी है तो उसका फैसला आज़ादी के बाद होना चाहिए जबकि मुस्लिम लीग की ज़िद थी कि पहले बंटवारा, उसके बाद आज़ादी। मुस्लिम लीग ने मिशन का प्लान इस हद तक मान लिया जिस हद तक उसमें मंज़ूरी दी गयी थी।

20 फरवरी 1947 को एटली ने ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देगी। नए वायसराय लार्ड माउंटबेशन को आधिकारिक किया गया और इस तरह एक नए युग की शुरूआत हुई, भारत पहुंचने के दो माह के भीतर ही माउंटबेटन ने अपनी पॉलिसी ज़ाहिर की, यह पॉलिसी भारत को दोहरी डोमीनियन हैसियत देना और 15 अगस्त 1947 तक सत्ता हस्तांतरण की तारीख का एलामिया है कि साम्प्रदायिकता जिसको ब्रिटिश सरकारों ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया था वही साम्प्रदायिकता उनकी सरकार के पतन का कारण बनी और संघर्ष से भरा तारीखी समय भी आया जब ''पूरा विश्व सोया हुआ था लेकिन भारत जाग रहा था और आज़ादी प्राप्त कर रहा था और 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को आज़ादी और बंटवारे की दोहरी हक़ीक़त इस उपमहाद्वीप की इतिहास बन गया। एक लम्बी लड़ाई और अनगिनत लोगों की कुर्बानी से भरे दौर ने हमको आज़ादी की नेअमत से नवाज़ दिया और आख़िरकार 1857 में जो चिंगारी शोला बनी थी उसकी आग ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दीं। 1947 तक भारत ने बाज़ुए क़ातिल के ज़ोर को बार-बार चैलेंज किया और सरफरोशी की तमन्ना ने ग़ैर मुल्की सरकार को भारत से उखाड़ फेंका।

यह किस क़दर अफसोस की बात है कि वतन से प्यार करने वाले लाखों सरफरोशों ने जिन में हिन्दू भी थे और मुसलमान भी, अमीर भी थे और ग़रीब भी थे अपने खून का दरिया बहाकर आज़ादी की जिस नेमत को प्राप्त किया था आज हमारे देश के कुछ नासमझ और भीक की टुकड़ों पर पलने वाले लोग इस आज़ादी को 'भीक' कहकर उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं।

फिल्म एक्ट्रेस कंगना राणावत भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मोदी सरकार से पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद कहा है कि 1947 में देश को आज़ादी नहीं भीक मिली थी। असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, जो पूरी तरह देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो जाने वाले लाखों मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन ही नहीं बल्कि देश के साथ खुली गद्दारी है। भाजपा के ही नेता वरुण गांधी का यह प्रश्न काफी अहम है कि कंगना की इस बकवास को गद्दारी कहूं या पागलपन? वरुण गांधी ने कुछ चश्मपोशी से काम लिया जबकि वाक़ेआ यह है कि यह खुली गद्दारी है।

यह सितम ज़रीफी भी मुलाहज़ा करते चलें कि एक तरफ तो मोदी सरकार आज़ादी का 75वां जश्न मना रही है और दूसरी ओर मोदी भक्त आज़ादी को 'भीक' बता रहे हैं, यहां प्रश्न यह है कि आख़िर हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्या वह नहीं जानते कि उनकी चुप्पी ऐसे लोगों को आहार परोस रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को अपने इन भक्तों से सहमत नहीं है तो उन्हें चुप्पी तोड़कर ऐसी बकवास पर लगाम लगानी चाहिए और वह भी ऐसा समझते हैं कि जिसकी हमें हर हाल में उम्मीद नहीं है तो फिर तो इस देश का खुदा ही हाफिज़ है।❑❑

शेष.... क्या क्षत्रपों के राष्ट्रीय नेता....

ममता बनर्जी ने बंगाल के बाहर पांव पसारने की रणनीति पर काम तेज़ कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बाहर गोवा में उन्हें अपने लिए मुफीद मौक़ा नज़र आ रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने राज्य में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री रहे फलेरियो को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके पहले वे राहुल गांधी की युवा बिग्रेड की सदस्य रही असम की लोकसभा सांसद सुष्मिता देव को न सिर्फ तृणमूल में शामिल कर चुकी हैं, बल्कि उन्हें पश्चिमी बंगाल से राज्यसभा में भी भेज दिया है।

ममता बनर्जी भाजपा के विरोध में कांग्रेस का साथ भी है, लेकिन अपने विस्तार की योजना में वे उसी कांग्रेस की परवाह भी नहीं कर रही है। क्षेत्रीयता की सीमाओं से मुक्त होने की कोशिशों में शरद पवार भी शिद्दत से जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी सीमा यह है कि वे अपने ही राज्य महाराष्ट्र में वैसा सर्वमान्य जन समर्थक आधार हासिल करने में सफल नहीं हुए हैं, जैसा ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हासिल है। शरद पवार अपनी घड़ी की टिक-टिक सुनाने की कोशिश महाराष्ट्र की सीमा से बाहर भी करते रहते हैं सोनिया गांधी के विदेशी मूल को आधार बनाकर जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, तब उनके साथ मेघालय के दिगगज पी.ए. संगमा भी थे, उनके साथ बिहार के तारिक अनवर भी थे। तब राकांपा की किंचित हल्की ही सही, धमक महाराष्ट्र के बाहर बिहार और मेघालय में भी सुनाई देती थी।

भले ही उसके पीछे स्थानीय गठबंधनों का भी सहयोग होता था, इसके अलावा गोवा में भी उनके एक दो विधायक चुने जाते रहे। लेकिन बाद में संगमा ने अपनी अलग राह चुन ली और तारिक अनवर ने पुरानी कांग्रेस में ही अपना भविष्य तलाश लिया। क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होने होने की कोशिश में जनता दल (यू.) भी लगा हे। जिस जनता पार्टी और जनता दल का वह अंश है, अतीत में उनका क़द बहुत बड़ा होता था। 1977 के चुनाव में तो जनता पार्टी ने 271 सीटें जीतीं थीं, जबकि 1989 में उसे 140 सीटें मिली थीं।

लेकिन उसके बाद बाद से जनता दल लगातार छीजता चला गया। इसके इतने टुकड़े हुए कि उसके बारे में कहा जाने लगा कि इस दल के हजार हुए कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नेशनल लोक दल आदि जनता दल से ही अलग होकर बने दल हैं। जनता दल से अलग होकर बने दलों ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की है। इंडियन नेशनल लोकदल इसका अपवाद है, जिसके नेता ओम प्रकाश चौटाला ने इस सदी के शुरू के दिनों में ऐसी कोशिश की थी। राष्ट्रीय बनने की कोशिश में कौन सफल होगा, यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है लेकिन एक बात तो यह है कि यह राह तीनों ही दलों के लिए आसान नहीं होगी।❑❑

शेष.... टीम को मुश्किलों से पार....

का परिणाम था कि भारत एक साथ इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों के ख़िलाफ़ सीरीज खेलने में सफल हुआ। द्रविड़ के मुख्य कोच के कार्यकाल के दौरान एक और चुनौती आने वाली हैं मौजूदा टीम में कई खिलाड़ी 33 से 35 वर्ष के बीच के हैं उनका कैरियर साल-दो साल से लेकर चार वर्ष का ही शेष है। इनमें चेतेश्वर पुजारा, अंजिक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। द्रविड़ को समय रहते इन खिलाड़ियों के कम से कम दो-दो विकल्प तैयार करने होंगे।

भारतीय कप्तान विराट कोहली 33 वर्ष के हैं और टी-20 के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा 34 वर्ष के। इनके अभी चार-पांच वर्ष और खेलने की उम्मीद की जा रही है इसलिए द्रविड़ के सामने भविष्य का कप्तान तैयार करने की चुनौती भी होगी। इसके लिए उनके पास के.एल. राहुल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं। ज़रूरत उन्हें इस भूमिका के लिए तैयार करने की है। आम राय भी यही है कि द्रविड़ यह काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **28 Nov.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•भुखमरी का आईना•बारिश से आपदा•शिक्षा का असर

भुखमरी का आईना

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में भूख से दोचार लोगों की त्रासदी पर अदालतों को निर्देश देना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह हे कि जिस समस्या से लड़ना और उसे ख़त्म करना सरकार की पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज भी वह मसले पर प्रश्नों के कठघरे में खड़ी हैं। यह हालत तब है, जब देश में सरकार की बुनियाद ही लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। लेकिन आंकड़ों से लेकर ज़मीनी तस्वीर तक यह बताती है कि भूख से मौतों को लेकर सरकारें कितनी फिक्रमंद रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों साफ लहज़े में कहा कि भूख से एक भी मौत न हो, यह सुनिश्चित करना एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। हो सकता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए फिर से मौजूदा या नए उपायों पर काम करने की बात करें, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक लोकतांत्रिक सरकार को असहज करने क लिए काफी नहीं है? अदालत ने केन्द्र सरकार को अंतिम अवसर के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर सामुदायिक रसोई पर अखिले भारतीय नीति तैयार करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। ज़ाहिर है, सामुदायिक रसोई जैसी व्यवस्था उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो किन्हीं वजहों से अपना और अपने परिवार का पेटभर पाने में नाकाम होते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास आय का नियमित ज़रिया हो, तो शायद उन्हें महज़ भूख मिटाने के लिए किसी व्यक्ति या सरकारी कार्यक्रम पर निर्भरता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदालत ने सरकार के लिए यह उचित टिप्पणी की है कि अगर आप भूख का ख़्याल रखना चाहते हैं, तो कोई संविधान, कोई कानून आपको मना नहीं करेगा। विचित्र है कि जब इस मामले की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तब अक्सर सरकार आनन फानन में कुछ चिह्नित तबक़ों के लिए सीमित अवधि की ख़ातिर अनाज वितरण के किसी नए कार्यक्रम की घोषणा कर देती है, लेकिन समस्या की जड़ों के तौर पर भूख से दोचार लोगों और समूहों के लिए नियमित रोज़गार और आय के अभाव के बारे में सोचना और उसे दूर करने को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं दिखता। जबकि औपचारिक महत्व की आधी अधूरी पहलक़दमी के नतीजे समस्या के दीर्घकालिक और ठोस समाधान नहीं हो सकते।

भूख से मौतों की समस्या देश में अनाज, संसाधनों की कमी की वजह से है या फिर यह सरकारों की इच्छाशक्ति और अदूरदर्शिता का नतीजा है। सरकार को यह सोचना होगा कि आख़िर किन वजहां से कुपोषण के मामले में बदतर हालत में होने के साथ साथ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 116 देशों में 101वें स्थान पर क्यों है?

अदालत में अटार्नी जनरल ने यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ढांचे के भीतर कुछ काम किया जा सकता है और अदालत ने भी इससे सहमति जताई कि योजना के लिए वैधानिक ढांचा होना चाहिए, ताकि नीति में बदलाव पर इसे बंद नहीं किया जा सके। यह ध्यान भी रखने की ज़रूरत है कि जब तक राज्यों को किसी योजना के अमल में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। प्रश्न यह है कि नागरिकों को भोजन का अधिकार देने वाले क़ानून के लंबे समय से लागू होने के बावजूद आज भी देश में भूख से होने वाली मौतें चिंता का विषय क्यों बनी हुई हैं। दरअसल, अब तक सरकारों का जो रुख़ रहा है, अगर उस पर ग़ौर किया जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता है कि भूख से मौतों की समस्या देश में अनाज, संसाधनों की कमी की वजह से है या फिर यह सरकारों की इच्छाशक्ति और अदूरदर्शिता का नतीजा है। सरकार को यह सोचना होगा कि आख़िर किन वजहां से कुपोषण के मामले में बदतर हालत में होने के साथ साथ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 116 देशों में 101वें स्थान पर क्यों है?

बारिश से आपदा

पिछले दिनों दक्षिण भारत के अनेक इलाके बारिश से परेशान रहे। बंगलुरु और चेन्नई के अनेक इलाकों में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि नाव चलाकर लोगों को राहत देने की नौबत आई, विशेषकर तमिलनाडू की राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र मनाली में कई घरों में पानी घुस गया। उत्तरी चेन्नई में पड़ोस के कई हिस्से नदी में ज़्यादा पानी आने से जलमग्न हो गए। बारिश से आंध्र प्रदेश में भी बुरा हाल हो गया, जहां 30 से अधिक लोगों को मौत के काल में ले गई और अनेक बुरी तरह प्रभावित हुए। ज़्यादातर जलाशय भर गए और उनके दरवाज़े खोलने पड़े, जिससे आसपास की झीलों में पानी लबालब भरकर बहने लगा है। फ्लार नदी में विगत 60 सालों में कभी इतना पानी नहीं आया था। बड़ा प्रश्न यह है कि 24 घंटे में 153 मिमी बारिश का क्या इशारा है? ऐसे प्रतिकूल मौसम का विस्तार से अध्ययन ज़रूरी है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन मौसम विज्ञानियों के साथ ही अन्य संबंधित वैज्ञानिकों को भी अध्ययन के लिए तैनात कर देना चाहिए। चिंता इसलिए भी ज़्यादा है, क्योंकि हवाई सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी से बारिश के अनुकूल माहौल बना। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू और कर्नाटक, चारों ही राज्यों में इस मौसम में लौटते मानसून की बारिश होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश से प्रभावित रही। यह अध्ययन का विषय है, इसे केवल प्राकृतिक घटना या आपदा के रूप में नहीं लिया जा सकता। मौसम विभाग लगातार वर्षा के चेतावनी देता आ रहा है। बेशक, भारत में विशेष रूप से शहरों से संबंधित विशेष योजना बनाने की ज़रूरत है। कभी दिल्ली, तो कभी मुंबई, कभी पटना व अन्य शहरों में बारिश से बुरा हाल हो जाता है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शहरों में जल निकारी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी स्थिति जल भराव न हो। दिक्कत यह है कि ज़्यादातर स्थानीय निकायों के ज़िम्मे ही यक काम छोड़ दिया जाता है। शहरी निकायों के सोचने का तरीक़ा अलग होता है, अधिकारी सोचते हैं कि वर्षा के कारण वर्ष में दस या पन्द्रह दिन ही समस्या रहेगी, अत: 15 दिन की परेशानी से बचने के लिए कोई ठोस स्थायी उपाय क्यों आज़माया जाए? अधिकारी सोचते हैं कि बारिश का पानी भरा है तो कुछ ही दिन में उतर जाएगा और लोग भी अपनी परेशानी भूल जाएंगे। देश में अनेक शहर हैं, जहां जल निकासी के लिए सड़कों से सटी सामान्य नालियां तक नहीं हैं। जहां नालियां हैं, वहां उनकी उचित साफ सफाई नहीं होती है। कचरा प्रबंधन खराब है, इसके चलते भी जल निकासी मुश्किल हो जाती है। शहर के लोगों को अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए कि पानी की राह में कौन रोड़ा बन रहा है? कभी हर शहर में कई-कई तालाब हुआ करते थे, वे अब कहां हैं? जिस दिन हम इन बुनियादी प्रश्नों का जवाब खोजने लगेंगे, उस दिन पानी शहरों के लिए मुसीबत नहीं, वरदान होने लगेगा।

शिक्षा का असर

ग़ैरलाभकारी संस्था प्रथम द्वारा जारी एनुअल स्टेटंस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट (असर) 2021, जो 25 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में टेलीफोन से किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है, एकाधिक अर्थों में उल्लेखनीय है और बताती है कि महामारी की दो लहरों ने ग्रामीण भारत की स्कूली शिक्षा पर कैसा असर डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में नामांकन बढ़ा है - छात्रों के स्कूल से बाहर होने का जो आंकड़ा 2018 में चार ओर 2020 में 5.5 प्रतिशत था, वह 2021 में 4.9 प्रतिशत रह गया है और ऑनलाइन कक्षाओं को देखते हुए छात्रों में डिजिटल विभाजन भी कम हुआ है -वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत बच्चों के पास मोबाईल था, जो 2020 में बढ़कर 61.8 फीसद और 2021 में 67.6 फीसदी हो गया। पर इस रिपोर्ट का सबसे उल्लेखनीय पहलू है सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ना। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2018 में 64.3 छात्र थे, जो 2020 में बढ़कर 65.8 हो गए और इसे वर्ष नामांकन और बढ़कर 70.3 फीसदी हो गया, यह कोविड से पहले के स्तर से भी अधिक 32.5 फीसदी था, वह 2020 में घअकर 28.8 फीसदी तथा 2021 में और घटकर 24.4 प्रतिशत रह गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश और केवल जैसे राज्यों के सरकारी स्कूलों में नामांकन

ग्रामीण भारत में स्मार्टफोनों की संख्या भले ही दोगुनी हो गई है, पर स्कूली बच्चों और उसमें भी निचली कक्षा के छात्रों तक इसकी पहुंच अब भी कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है, जहां के बच्चों की स्मार्टफोन तक पहुंच सबसे कम है। ज़ाहिर है, इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त कमियां दूर की जाएं, तो परिदृश्य और बेहतर हो सकता है।

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान
आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।
रक़म भेजने के तरीक़े:-
❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा
वार्षिक Rs.130/-
6 महीने के लिए Rs.70/-
एक प्रति Rs.3/-
जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173